मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं नई दिल्ली से एक साथ प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र

हमारा उद्देश्य सेवा समर्पण जनकल्याण

एक सत बुलेटिन

E-mail: eksatbulletin@gmail.com | मुरैना, मंगलवार 24 नवंबर 2026 | वर्ष-01, अंक-24, पृष्ठ-08, मूल्य- दो रुपए | Website: www.eksatbulletin.in

सरयू-कमला एक्सप्रेस का शुभारंभ



मुख्यमंत्री डॉ.यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिए गए अनेक निर्णय

प्रदेश के समग्र विकास, जनकल्याण के लिए 7 हजार करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति

एक सत बुलेटिन, भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में सम्पन्न हुई। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री चेतन्य कुमार काश्यप ने मंत्रि-परिषद के निर्णयों की जानकारी दी। मंत्री श्री काश्यप ने बताया कि मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के समग्र विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और जनकल्याण के लिए 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और उन्नत देशी गौवंश को बढ़ावा देने के लिए 'गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना' के क्रियान्वयन का अनुसमर्थन किया गया। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के 9 कमजोर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए अंशपूंजी सहायता के रूप में 325 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी



समितियों के ड्यू हो चुके निर्वाचन की अवधि एक वर्ष आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद ने बैठक में भारत सरकार की आरडीएसएस योजना के पहले चरण में प्रदेश की 1,834 बसाहटों के 46 हजार से अधिक अविद्युतीकृत घरों और 54 शासकीय सार्वजनिक संस्थानों के विद्युतीकरण के लिए 193करोड़72लाख रुपये की कार्ययोजना को मंजूरी दी गई। प्रदेश में खनिज अन्वेषण नीति के क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त करने की भी स्वीकृति दी गई। मंत्रि-परिषद ने 'वेदान्त पीठ की स्थापना' के अंतर्गत ओंकारेश्वर स्थित एकात्म धाम में ₹अद्वैत लोक₹ के निर्माण के लिए 16वें वित्त आयोग की अवधि वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 के लिए 2,278 करोड़ 99 लाख रुपये मंजूर किए हैं। इसी अवधि के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की 23 योजनाओं को निरंतर रखने के लिए 3,059 करोड़ 7 लाख रुपये तथा मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान से संबंधित योजना को जारी रखने के लिए 1 हजार 165 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के 9 कमजोर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए अंशपूंजी सहायता के रूप में 325 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। रीवा, सतना, दतिया, शिवपुरी और जबलपुर के 5 कमजोर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में 25-25 करोड़ रुपये की अंशपूंजी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही मंत्रि-परिषद ने 4 अन्य कमजोर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधारने का भी निर्णय लिया है। इसके तहत रायसेन, मुरैना, सागर और सीधी के जिला बैंकों को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में 50-50 करोड़ रुपये की अंशपूंजी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

अयोध्या-जनकपुर ट्रेन का पहला सफर: मोदी-बालेन ने हरी झंडी दिखाई

एजेन्सी, नई दिल्ली

भगवान राम की नगरी अयोध्या और माता सीता के जनकपुर धाम के बीच पहली ट्रेन आज से शुरू हो गई। प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने हरी झंडी दिखाकर सरयू कमला एक्सप्रेस को रवाना किया।

ट्रेन करीब साढ़े तीन घंटे का सफर करके शाम करीब 4.50 पर गोरखपुर पहुंची। ट्रेन को शाम 5.10 बजे पहुंचना था, जो करीब 20 मिनट पहले ही पहुंच गई। यह ट्रेन यूपी और बिहार के 10 स्टेशनों पर रुकेगी। पहले दिन 1158 यात्री इसमें सवार हुए। आम यात्रियों के लिए यह ट्रेन 28 नवंबर से शुरू होने की उम्मीद है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक, राजा दशरथ राम बारात लेकर जब मिथिला में जनकपुर पहुंचे थे, तब उन्हें 4 दिन लगे थे। अब यही सफर करीब 19 घंटे में पूरा होगा।

जनकपुर में ट्रेन के स्वागत की तैयारी

सरयू-कमला एक्सप्रेस अयोध्या से 19 घंटे के सफर के बाद जनकपुर पहुंचेगी। यह अयोध्या से जनकपुर पहुंचने वाली पहली ट्रेन होगी। ट्रेन और यात्रियों के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। स्टेशन की दीवारों पर रंग-रोगन किया जा रहा है। स्टेशन के बाहर बंदनवार लगाए जाएंगे।

सीएम योगी ने बताया एकता का प्रतीक

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस नई रेल सेवा पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सरयू-कमला एक्सप्रेस के शुरू होने से अयोध्या और मिथिला के बीच सदियों पुराना सांस्कृतिक रिश्ता एक बार फिर मजबूत हुआ है. उन्होंने कहा कि अब नेपाल के श्रद्धालु आसानी से भगवान श्रीराम के दर्शन के लिए अयोध्या आ सकेंगे, जबकि भारतीय श्रद्धालु माता जानकी की पूजा-अर्चना के लिए सीधे जनकपुर धाम पहुंच सकेंगे।

शेख हसीना की पार्टी पर फिर शिकंजा

पूर्व मंत्रियों समेत छह बड़े नेताओं को जेल भेजने का आदेश

एजेन्सी, ढाका

बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाने वाले जुलाई-अगस्त 2024 के जनविद्रोह के दौरान कथित मानवता-विरोधी अपराधों से जुड़े एक मामले में अवामी लीग के छह वरिष्ठ नेताओं को जेल भेजने का आदेश दिया है। इनमें पार्टी की प्रेसिडियम के सदस्य अमीर हुसैन अमू भी शामिल हैं। न्यायाधिकरण ने इसी मामले में अवामी लीग के संगठन सचिव मिर्जा आजम को पेश होने का निर्देश देते हुए दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित करने का भी



आदेश दिया। न्यायमूर्ति एमडी नजरुल इस्लाम चौधरी की अध्यक्षता वाली अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-2 की तीन सदस्यीय पीठ ने रविवार को ये आदेश दिए।

अन्य आरोपियों में पूर्व नौवहन मंत्री शाजहान खान, पूर्व नागरिक उड्डयन एवं पर्यटन मंत्री लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) फारुक खान, पूर्व कृषि मंत्री अब्दुर रज्जाक, हसीना के पूर्व बिजली, ऊर्जा एवं खनिज संसाधन सलाहकार तौफीक-ए-इलाही चौधरी और पूर्व मंत्री डॉ. दीपू मोनी शामिल हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार, छह में से पांच आरोपियों को रविवार सुबह न्यायाधिकरण के समक्ष पेश किया गया, जबकि बीमारी के कारण फारुक खान को अदालत नहीं लाया जा सका।

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, सुनवाई के दौरान अभियोजक अब्दुस सत्तार पलोवान ने न्यायाधिकरण को बताया कि छह आरोपियों को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया था।

40 से 50 दिनों में वैकल्पिक मार्ग का निर्माण प्रस्तावित

जबलपुर-भोपाल मार्ग के यातायात को मिलेगी सुगमता, मटर उत्पादक किसानों सहित आम नागरिकों को होगा लाभ

एक सत बुलेटिन, जबलपुर

जबलपुर से भोपाल को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग पर शहपुरा में लंबे समय से बनी जाम की समस्या से आम नागरिकों, वाहन चालकों और क्षेत्रीय किसानों को शीघ्र राहत मिलने की उम्मीद है। शहपुरा रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के निर्माण में हो रही देरी और इसके कारण प्रतिदिन उत्पन्न होने वाली यातायात संबंधी परेशानियों को देखते हुए लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए शहपुरा आरओबी के समीप नहर के किनारे से लगभग 9 किलोमीटर लंबे वैकल्पिक सड़क मार्ग के निर्माण की योजना तैयार कराई है। इस मार्ग के निर्माण को आगामी 40 से 50 दिनों में पूरा करना प्रस्तावित किया गया है।

इसी प्रस्तावित वैकल्पिक मार्ग की स्थिति, निर्माण की संभावनाओं और यातायात व्यवस्था का जायजा लेने के लिए लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने आज शहपुरा, पाटन रोड एवं सहजपुर मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ मौके



पर पहुंचकर मार्ग की भौगोलिक स्थिति, उपलब्ध भूमि, नहर के किनारे सड़क निर्माण की संभावनाओं तथा यातायात के वैकल्पिक संचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आम जनता को जाम की समस्या से जल्द से जल्द राहत दिलाना प्राथमिकता है, इसलिए सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर वैकल्पिक मार्ग के निर्माण की प्रक्रिया को गति प्रदान करें।

निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने बताया कि शहपुरा में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चलने और उसके चलते यातायात प्रभावित होने से जबलपुर-भोपाल मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ रहा है। विशेष रूप से व्यस्त समय और मटर के सीजन में यहां जाम की स्थिति निर्मित होती है, जिससे आम नागरिकों, व्यापारियों, किसानों और अन्य वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

नहर के किनारे बनेगा 9 किमी लम्बा वैकल्पिक मार्ग

श्री राकेश सिंह ने बताया इस समस्या का व्यावहारिक समाधान निकालने के उद्देश्य से रिंग रोड के समीप एनएच -45 पर ग्राम खेरी के पास एनएचएआई द्वारा निमार्णाधीन रेलवे ओवरब्रिज से नहर के किनारे होते हुए जबलपुर-पाटन रोड के घूँसौर तक लगभग 9 किलोमीटर लंबा वैकल्पिक मार्ग तैयार करने की योजना बनाई गई है। प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई करीब 7.5 मीटर रखी जाएगी, जिससे वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से हो सके। उन्होंने कहा कि विकास का वास्तविक उद्देश्य नागरिकों के जीवन को सुगम बनाना और उनकी रोजमर्रा की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना है। शहपुरा में जाम की समस्या लंबे समय से क्षेत्र के लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। ऐसे में रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की प्रक्रिया पूरी होने तक यातायात को व्यवस्थित रखने के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार करना आवश्यक है। यह मार्ग न केवल तत्कालीन यातायात समस्या का समाधान बनेगा, बल्कि भविष्य में भी क्षेत्रीय आवागमन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

टीएमसी के नाम और चुनाव चिन्ह पर घमासान

ममता गुट की रितब्रत, अरूप रॉय पुलिस अफसरों के खिलाफ शिकायत

एजेन्सी, कोलकाता

ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी गुट ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद के बीच रितब्रत बनर्जी और अरूप रॉय समेत कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। ममता गुट ने आरोप लगाया है कि विरोधी गुट ने चुनाव आयोग के सामने पेश करने के लिए फर्जी दस्तावेज और हलफनामे तैयार किए हैं। यह शिकायत कोलकाता के कालीघाट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। दोनों गुटों ने चुनाव आयोग के सामने पार्टी के नाम, चुनाव चिन्ह और बैंक खातों पर अपना दावा पेश करते हुए हलफनामे जमा किए हैं। ममता गुट का आरोप है कि बीरभूम जिले के नानूर पुलिस स्टेशन के कुछ पुलिस



अधिकारियों की मिलीभगत से विरोधी गुट ने फर्जी हलफनामे तैयार किए।

ममता-एआईटीसी की ओर से अधिवक्ता सुभाशिष चक्रवर्ती ने यह शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पुलिस अधिकारियों और सिविक वॉलंटियर्स ने फर्जी दस्तावेज तैयार करने में मदद की। ममता गुट ने दावा किया है कि नानूर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने रितब्रत बनर्जी और अरूप रॉय के साथ मिलकर फर्जी और मनगढ़ंत हलफनामे तैयार किए।

सीएम शुभेंदु ने बिजली बिल पर भी किया बड़ा एलान

बंगाल में गौ हत्या पर प्रतिबंध: गोशालाओं को मिलेगी आर्थिक मदद

एजेन्सी, नई दिल्ली

पश्चिम बंगाल में गोवंश संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा एलान किया है। उन्होंने साफ कहा है कि राज्य में गोहत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस पर रोक लगाने के लिए सरकार नया विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही बुजुर्ग और बीमार गायों की देखभाल करने वाली गोशालाओं को सालाना एक लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। सोमवार को नवान्न में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने इन फैसलों की जानकारी दी। बैठक में रोजगार, युवाओं की आर्थिक मदद और बिजली बिल से जुड़े कई अहम फैसले भी लिए गए।

गोहत्या रोकने के लिए क्या कदम उठाएगी सरकार?

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहले से ही पशु वध नियंत्रण कानून लागू है, लेकिन इसके बावजूद कुछ जगहों पर चोरी-छिपे गोहत्या की शिकायतें मिल रही हैं। सरकार अब ऐसी गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाएगी। उन्होंने 1950 के पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण कानून का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। सरकार नया विधेयक लाने की भी तैयारी कर रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने कुछ अहम फैसलों की जानकारी दी।

गोहत्या पर रोक: चोरी-छिपे गोहत्या करने वालों के खिलाफ सख्ती की जाएगी।

गोशालाओं को मदद: गोकुल मिशन के तहत बुजुर्ग और बीमार गायों की देखभाल, इलाज और पालन-पोषण के लिए सालाना अधिकतम एक लाख रुपये मिलेंगे।

पशु खरीद में सहायता: दुधारू पशुओं की खरीद के लिए भी मदद देने का प्रावधान किया गया है। योजना की विस्तृत जानकारी पशुपालन विभाग जारी करेगा।

मंत्रिमंडल ने अलग-अलग सरकारी विभागों में 10,146 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। इनमें पुलिस और ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के 9,250 पद शामिल हैं। इनके तहत 650 सब-इंस्पेक्टर, 8,000 कांस्टेबल और 600 राइफलमैन की नियुक्ति होगी। एंटी-नारकोटिक्स विभाग में 48 और साइबर क्राइम विभाग में 160 पद भरे जाएंगे।



पंचायत, ग्रामीण विकास, पर्यटन और शहरी विकास विभागों में भी भर्ती होगी। सरकार ने आगे एक लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा है। नई भर्ती परीक्षाओं में आवेदन और परीक्षा शुल्क भी नहीं देना होगा। पहले सामान्य वर्ग के लिए 500 और एससी-एसटी उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये तक शुल्क था।

युवासाथी की जगह कौन-सी योजना आएगी?

युवासाथी योजना का नाम बदलकर भरोसा किया जाएगा। जनवरी 2027 से अगले 15 महीने तक पात्र स्नातक और सरकारी तकनीकी संस्थानों में प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को हर महीने 2,000 रुपये मिलेंगे। अन्य पात्र गैर-स्नातक युवाओं को 1,500 रुपये दिए जाएंगे। पहले से डिजिटाइज किए गए 54 लाख आवेदनों का सत्यापन होगा। आधार से जुड़े बैंक खाते, उम्र और शैक्षणिक योग्यता की जांच के बाद लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी। यह काम 31 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। एक परिवार के अधिकतम दो लोग लाभ ले सकेंगे। अन्नपूर्णा योजना के तहत 3,000 रुपये मासिक पाने वाली महिलाएं इसके लिए पात्र नहीं होंगी।

शीतकालीन सत्र में कौन-से विधेयक पेश होंगे?

विधानसभा का शीतकालीन सत्र 4 से 14 दिसंबर तक चलेगा। इसमें पंचायत कानून, भूमि सुधार, कारोबार को आसान बनाने, दुकानों और प्रतिष्ठानों तथा श्रमिक सुरक्षा से जुड़े आठ विधेयक पेश करने की तैयारी है। पूर्व विधायकों का चिकित्सा भत्ता 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का प्रस्ताव भी है। अनाथालयों और दिव्यांगों के आवासीय संस्थानों में भोजन के लिए दैनिक अनुदान 56 से बढ़ाकर 110 रुपये कर दिया गया है, जो एक दिसंबर से लागू होगा। रामकृष्ण मिशन के कुछ और शैक्षणिक संस्थानों, कॉलेजों और सेवा केंद्रों को भी सालाना आर्थिक सहायता मिलेगी। गोहत्या पर प्रस्तावित कानून और बाकी योजनाओं का अंतिम स्वरूप सरकारी विधेयकों और दिशा-निर्देशों के बाद स्पष्ट होगा।

मुख्यमंत्री ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बताया कि जनवरी 2027 से पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के उपभोक्ताओं को हर महीने बिजली बिल मिलेगा। अभी तीन महीने में एक बार बिल जारी होता है। अब मीटर की रीडिंग भी हर महीने होगी। मुख्यमंत्री ने निजी बिजली कंपनी सीईएससी से भी ऐसी ही व्यवस्था अपनाने का अनुरोध करने की बात कही। औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में पिछले छह महीनों के दौरान बिजली की खपत बढ़ी है। इसे देखते हुए दिसंबर से अतिरिक्त बिजली खरीदी जाएगी। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुली निविदा होगी और सबसे कम बोली लगाने वाले आपूर्तिकर्ता से बिजली खरीदी जाएगी।

खाद्य मंत्री राजपूत ने बीना में किया नवनिर्मित संयुक्त अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय भवन का लोकार्पण

बीना ने विश्व पटल पर बनाई अपनी विशिष्ट पहचान, जिला बनने का हकदार: गोविंद सिंह

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बीना में लगभग 11 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से निर्मित नवनिर्मित संयुक्त अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय भवन का विधि-विधान से पूजन कर रिबन काटकर लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि नवनिर्मित भवन से बीना क्षेत्र के आमजन को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवाएं सुगमता से मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रशासन को जनता के करीब लाना और जनसेवाओं को सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाना है। उन्होंने कहा कि बीना के विकास के लिए अधोसंरचना को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि वे बीना को जिला बनाने के प्रबल पक्षधर हैं। बीना ने देश के साथ-साथ विश्व पटल पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। एरण, बीना रिफायनरी और जंक्शन बीना की पहचान के प्रमुख केंद्र हैं। उन्होंने नवनिर्मित सर्वसुविधायुक्त संयुक्त अनुविभागीय कार्यालय भवन के लोकार्पण पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही एरण के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। एरण को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बीना वासियों से बीना के सर्वांगीण विकास के लिए मिलजुल कर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना



से आमजन को उनके घर का मालिकाना हक मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के जनहितैषी प्रयासों से स्वामित्व योजना के माध्यम से आज जन-जन को अपने घर की निःशुल्क रजिस्ट्री प्राप्त हो रही है। अनुविभागीय कार्यालय भवन विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि : श्री अग्रवाल

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद रजनीश अग्रवाल ने कहा कि नवनिर्मित संयुक्त अनुविभागीय कार्यालय भवन बीना के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे अधिकारियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा और आमजन को एक ही स्थान पर सेवाएं मिलने से प्रशासनिक कार्यों में गति आएगी। उन्होंने अपनी सांसद निधि से कार्यालय परिसर में टीन शेड बनवाने की घोषणा की। साथ ही कहा कि बीना के शासकीय स्कूल, कॉलेज और अन्य शासकीय भवनों में शौचालय निर्माण के लिए भी सांसद निधि से राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने भवन एवं परिसर में साफ-सफाई और समुचित व्यवस्था बनाए रखने को कहा।बीना विधायक निर्मला सप्रे ने कहा कि नवनिर्मित संयुक्त अनुविभागीय कार्यालय भवन के लोकार्पण से बीना के प्रशासनिक ढांचे को नई पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि यह भवन बीना के विकास की दिशा में एक नई सीढ़ी साबित होगा। उन्होंने बीना के देश के विकास में योगदान का उल्लेख करते हुए भविष्य के विकास का खाका प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि विकास केवल सड़कों और भवनों के निर्माण तक सीमित नहीं है। आमजन को सुगम सुविधाएं मिलना ही विकास का सच्चा प्रतीक है। यह अनुविभागीय कार्यालय इसी विकास का प्रतीक बनेगा, जहां आमजन को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवाएं सुगमता से मिल सकेंगी।लोकार्पण समारोह को सांसद सागर संसदीय क्षेत्र श्रीमती लता वानखेड़े एवं गौरव सिरोठिया ने भी संबोधित किया।

भोपाल उत्सव मेले के उद्घाटन समारोह में समाजसेवी सुनील गर्ग को सम्मानित किया गया

मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सुनील गर्ग को निःस्वार्थ सेवाकार्यों के लिए मिला सम्मान

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

टीटी नगर के दशहरा मैदान में भोपाल उत्सव मेले के उद्घाटन समारोह में भोपाल में जनसेवा कार्यों के लिए समग्र अग्रवाल समाज के मुख्य संयोजक एवं समाजसेवी श्री सुनील गर्ग को सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में, संस्था के सदस्यों के बीच सुनील गर्ग को यह सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर समग्र अग्रवाल समाज की और से श्री होरीलाल गर्ग, श्रीमती मंजू गुप्ता, श्री मधुर अग्रवाल एवं श्री शरद अग्रवाल उपस्थित रहे । सुनील गर्ग ने यह सम्मान उन सभी कार्यकर्ताओं और सहयोगियों को समर्पित किया, जिन्होंने समाजहित के कार्यों में अपना समय और श्रम दिया है। उन्होंने कहा कि जब भी समग्र अग्रवाल समाज ने सेवा का कोई कार्य हाथ में लिया, उसे पूरा करने में अनेक लोगों का योगदान रहा। संस्था के सदस्यों के साथ उन सभी सहयोगियों को भी इसका श्रेय



जाता है, जो आवश्यकता पड़ने पर आगे आए और अपनी सामर्थ्य के अनुरूप हाथ बँटाया। जनसेवा के साथ समग्र अग्रवाल समाज, भोपाल, अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से नई पीढ़ी को जोड़ने में भी सक्रिय है। महाराजा अग्रसेन जयंती की शोभायात्रा में सुनील गर्ग ने मुख्य संयोजक की भूमिका निभाई थी। शोभायात्रा की रूपरेखा में समाज के अठारह गोत्रों का प्रतिनिधित्व और परिवारों की सामूहिक भागीदारी को विशेष स्थान दिया गया था।

वैशाली नगर सहित शहर में पेयजल के 121 नमूनों की जांच

भोपाल। शहरवासियों को स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम द्वारा जल नमूनों की जांच और जलापूर्ति व्यवस्था की निगरानी लगातार की जा रही है। सोमवार को वैशाली नगर से 11 और शहर के अन्य क्षेत्रों से 110 जल नमूने एकत्र कर मौके पर ही भौतिक परीक्षण किया गया। निगम के अनुसार सभी 121 नमूनों में पानी शुद्ध पाया गया। इन नमूनों को विस्तृत जांच के लिए निगम की आठ प्रयोगशालाओं में भेजा गया है। निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर जलकार्य विभाग के अधिकारियों और जल परीक्षण टीमों ने वैशाली नगर सहित विभिन्न क्षेत्रों में जलप्रदाय व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान पेयजल के नमूने लेकर मौके पर ही परीक्षण किया गया। साथ ही 16 स्थानों पर पाइपलाइन के लीकेज भी सुधारे गए। निगम के अनुसार वैशाली नगर में अब तक कुल 134 जल नमूनों का परीक्षण कराया जा चुका है। वहीं शहर के अन्य क्षेत्रों में अब तक 35 हजार 40 जल नमूने एकत्र कर उनकी जांच की गई है। पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए निगम द्वारा व्यापक स्तर पर सुधार कार्य भी किए जा रहे हैं।

13 दिसंबर को भोपाल में होगा 9वां अखिल भारतीय क्षत्रिय/राजपूत युवक-युवती परिचय सम्मेलन

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**



मध्य प्रदेश राजपूत समाज संस्था, भोपाल द्वारा 9वें अखिल भारतीय क्षत्रिय/राजपूत युवक-युवती परिचय सम्मेलन-2026 का आयोजन 13 दिसंबर, रविवार को महाराणा प्रताप भवन, चार इमली, मेन रोड नंबर-3, भोपाल में किया जाएगा। सम्मेलन के माध्यम से विवाह योग्य युवक-युवतियों को एक-दूसरे से परिचित होने और योग्य जीवनसाथी चुनने का अवसर मिलेगा। सम्मेलन के संयोजक हेमंत बहादुर सिंह परिहार ने समाज के सभी बंधुओं से अपील की है कि वे अपने विवाह योग्य पुत्र-पुत्रियों, भाई-बहनों एवं रिश्तेदारों का समय रहते पंजीयन कराएं तथा अपने परिचितों को भी इस आयोजन का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि परिचय सम्मेलन समाज में सुयोग्य एवं विश्वसनीय वैवाहिक संबंध स्थापित करने का एक सशक्त माध्यम है। 6 दिसंबर तक करा सकेंगे पंजीयन सम्मेलन के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक युवक-युवतियां संस्था की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन पंजीयन फॉर्म की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑनलाइन पंजीयन शुल्क 600 रुपये तथा ऑफलाइन पंजीयन शुल्क 800 रुपये निर्धारित किया गया है। ऑफलाइन शुल्क संस्था के कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। पंजीयन शुल्क में समाज की मासिक पत्रिका 'राजपूत दर्पण' का वैवाहिक विशेषांक तथा वर्ष 2027 का कैलेंडर भी शामिल है। पंजीकृत युवक-युवतियों के बायोडाटा रंगीन फोटो के साथ मासिक पत्रिका 'राजपूत दर्पण' में प्रकाशित किए जाएंगे।

रेलवे पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों की सुविधा के लिए 30 नवंबर तक जारी रहेगा विशेष अभियान

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल में रेल पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों की सुविधा के लिए संचालित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इस अभियान के अंतर्गत भोपाल मंडल में अब तक कुल 797 डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार किए जा चुके हैं। रेलवे पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया सरल एवं सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान 30 नवंबर 2026 तक संचालित किया जा रहा है।



अभियान के तहत मंडल के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों एवं रेलवे स्टेशनों पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां पेंशनरों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने में आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जा रहे विशेष शिविर भोपाल मंडल द्वारा पेंशनरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंडल रेल चिकित्सालय निशातपुरा, पॉलीक्लीनिक हबीबगंज, बीना, गुना एवं इटारसी के चिकित्सा संस्थानों तथा भोपाल, इटारसी, बीना, गुना एवं हरदा रेलवे स्टेशनों पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने के साथ-साथ पेंशनरों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं साइबर धोखाधड़ी से बचाव के संबंध में जागरूकता भी प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं एवं डिजिटल सेवाओं के उपयोग में आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। रेल प्रशासन ने पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों से अनुरोध किया है कि शिविर में आते समय अपना आधार कार्ड, मूल पेंशन भुगतान आदेश, बैंक पासबुक तथा आधार से लिंक सक्रिय मोबाइल फोन साथ लेकर आएं, ताकि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया सुगमता से पूरी की जा सके। भोपाल मंडल रेल प्रशासन सभी रेल पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों से अपील करता है कि वे 30 नवंबर 2026 तक चलने वाले इस विशेष अभियान का लाभ उठाने के लिए अपने निकटतम निर्धारित शिविर में पहुंचकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाएं।

भोपाल में वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो का निर्माण कार्य तेजी से जारी

146 करोड़ रुपये की लागत से प्रथम चरण में बनेंगी 6 नई लाइनें

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

भारतीय रेल में आधुनिक एवं उन्नत यात्री सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ रेलगाड़ियों के बेहतर रखरखाव के लिए आधारभूत संरचनाओं का भी निरंतर विकास किया जा रहा है। इसी दिशा में पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल में वंदे भारत ट्रेनों के अनुरक्षण एवं रखरखाव के लिए भोपाल कोच फैक्ट्री प्रांगण में अत्याधुनिक मेंटेनेंस डिपो का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के पूर्ण होने से भोपाल मंडल में संचालित होने वाली वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव की सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। रेलवे बोर्ड द्वारा 07 अक्टूबर 2025 को वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके पश्चात 13 जून 2026 से निर्माण



कार्य प्रारंभ किया गया। इस परियोजना को सितंबर 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रथम चरण में 146 करोड़ रुपये की लागत से बनेंगी 6 अनुरक्षण लाइनें परियोजना के प्रथम चरण में लगभग 146 करोड़ रुपये की लागत से 6 नई अनुरक्षण लाइनें विकसित की जा रही हैं। इन लाइनों के निर्माण से वंदे भारत ट्रेनों का आवधिक निरीक्षण एवं अनुरक्षण भोपाल में ही संभव हो सकेगा। इससे ट्रेनों के रखरखाव की क्षमता में वृद्धि होगी तथा आधुनिक ट्रेनों के अनुरक्षण के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वंदे भारत ट्रेनों के मध्यम एवं दीर्घकालीन अनुरक्षण की मिलेगी सुविधा वर्तमान में रानी कमलापति स्थित डिपो में वंदे भारत ट्रेनों का केवल साप्ताहिक निरीक्षण किया जा रहा है। प्रस्तावित नए मेंटेनेंस डिपो के निर्माण के बाद भोपाल में ही वंदे भारत ट्रेनों का मध्यम एवं दीर्घकालीन अनुरक्षण भी संभव हो सकेगा। इससे ट्रेनों के रखरखाव की व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी तथा अनुरक्षण संबंधी कार्यों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित होंगी। भारतीय रेल में रेलगाड़ियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसे देखते हुए उनके नियमित रखरखाव के लिए अतिरिक्त अनुरक्षण सुविधाओं का विकास भी आवश्यक है। इसी क्रम में निर्माणाधीन वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो में साक्करेकों के नियमित रखरखाव के लिए दो नई पिट लाइनों के निर्माण का भी प्रस्ताव किया गया है। इन नई पिट लाइनों के विकसित होने से साक्करेकों का नियमित अनुरक्षण कम समय में किया जा सकेगा। इससे एक ओर अधिक रेकों का रखरखाव सुगमता से संभव होगा, वहीं दूसरी ओर भोपाल जैसे प्रमुख स्टेशनों पर मौजूदा अनुरक्षण सुविधाओं पर दबाव भी कम होगा।

यह पार्क-संग्रहालय न केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का केंद्र

इस छोटी सी जनपद में शौर्य पार्क बनाने का जो निर्णय है, वह सराहनीय है: पटेल

■ एक सत बुलेटिन, **दमोह**

यहां देश के महापुरुषों और वीर योद्धाओं की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके अदम्य साहस, त्याग, बलिदान और राष्ट्र के प्रति समर्पण से प्रेरणा ले सकें। यह बात संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने तेंदूखेड़ा में मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग अंतर्गत 03 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले शौर्य स्मारक पार्क के भूमिपूजन के अवसर पर कही। राज्यमंत्री श्री लोधी ने कहा इस पार्क में अमर शहीद शंकर शाह, रघुनाथ शाह, वीरांगना रानी अवंती बाई एवं लोकमाता महारानी अहिल्याबाई की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। पार्क का निर्माण आकर्षक, दिव्य और भव्य स्वरूप में किया जाएगा। उन्होंने कहा संग्रहालय न केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का केंद्र बनेगा, बल्कि युवाओं में राष्ट्रप्रेम और वीरता की भावना जागृत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होने कहा महापुरुषों एवं वीरांगनाओं के त्याग, बलिदान, अदम्य साहस और राष्ट्र के प्रति समर्पण से प्रेरणा लेकर लोग देश, समाज और राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करने को प्रेरित होंगे। श्री लोधी ने कहा अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह ऐसे महान देशभक्त वीर थे, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते-हंसते अपने प्राण



न्योछावर कर दिए। उन्होंने कहा जब इन दोनों वीरों को तोप के मुंह से बांधकर उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई, तो उन्होंने ऐसी ओजस्वी पंक्तियां सुनाते हुए प्राण त्यागना स्वीकार किया, जिन्हें सुनकर लोगों के हृदय में देशभक्ति की ज्वाला धधक उठती है। ऐसे वीर बलिदानियों की गाथाएं समाज के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेंगी। जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल ने कहा इस छोटी सी जनपद में शौर्य पार्क बनाने का जो निर्णय लिया गया है, वह सराहनीय है। उन्होंने कहा जब यहां वीर सपूतों और वीरों की मूर्तियों का अनावरण होगा, तब आगे आने वाली पीढ़ी और युवा यहां आकर नमन करेंगे। उन्होंने कहा इससे आगे आने वाली पीढ़ी को यह भी पता चल सकेगा कि हमारे वीर सपूतों ने देश को स्वतंत्रता दिलाने में कितनी मेहनत की है। पाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैतान पाल ने कहा कि तेंदूखेड़ा की पावन धरा पर वीरांगना रानी अवंतीबाई, अमर शहीद राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह और लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमाएं स्थापित करने तथा भव्य शौर्य पार्क के भूमि-पूजन का यह कार्य अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने कहा अब तक अनेक सरकारें आई और गई, लेकिन राज्यमंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने वीरांगनाओं और शहीदों के सम्मान की चिंता करते हुए क्षेत्र को यह अनुपम सौगात दी है। उन्होंने कहा जब यह शौर्य पार्क बनकर तैयार होगा और यहां महान विभूतियों की प्रतिमाएं स्थापित हो जाएंगी, तब भारत माता की चिंता करने वाले बुजुर्गों के साथ-साथ विशेष रूप से नौजवानों के भीतर राष्ट्रप्रेम और देशभक्ति की नई चेतना जागृत होगी। इस अवसर पर सत्येंद्र सिंह लोधी और श्री कडप्पा ने भी अपने विचार विस्तार से रखें।

टीएल बैठक में विभागीय योजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा, बाजरा खरीदी के लिए सत्यापन कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश

शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करें मिशन मोड में कार्य करें अधिकारी: कलेक्टर

एक सत बुलेटिन, मुरैना

कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने सोमवार को आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों, शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं एवं विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कम प्रगति वाले विभागों को कार्य में तेजी लाने तथा आगामी टीएल बैठक तक निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुए नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन सहित अन्य राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति जानी। उन्होंने राजस्व कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। स्वामित्व योजना की धीमी प्रगति पर भी उन्होंने असंतोष व्यक्त किया तथा संबंधित अधिकारियों को सर्वेक्षण, सत्यापन एवं अभिलेख तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाकर



पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, टीबी मुक्त भारत अभियान एवं गैर-संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम सहित विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने-अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की नियमित निगरानी करें तथा पात्र हितग्राहियों का पंजीयन एवं लाभ वितरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कृषि आत्मनिर्भरता मिशन एवं राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए पृथक से बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी टीएल बैठक में इन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी, इसलिए सभी संबंधित अधिकारी अभी से लक्ष्य आधारित कार्ययोजना बनाकर कार्य करें। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविरों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण करने तथा निराकरण की जानकारी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अद्यतन दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिविरों में प्राप्त प्रत्येक आवेदन की नियमित निगरानी की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि आवेदकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने स्वीकृत पेयजल योजनाओं को शत-प्रतिशत पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं में राजस्व संबंधी बाधाएं आ रही हैं, उनका संबंधित राजस्व अधिकारी समन्वय से तत्काल निराकरण करें। राजस्व संबंधी कारणों से किसी भी योजना का कार्य बंद अथवा बाधित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा निर्धारित समय-सीमा में पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि पात्र वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए तथा पंचायत स्तर पर सचिवों एवं संबंधित मैदानी अमले के माध्यम से पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उनका पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र वरिष्ठ नागरिक आयुष्मान योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों के प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही समय पर पूर्ण कर आवास निर्माण की प्रगति बढ़ाई जाए।

मुरैना में 26 नवम्बर को होगा सिविल डिफेंस मॉक अभ्यास, हवाई हमले की चेतावनी एवं ब्लैकआउट की तैयारियों का होगा परीक्षण



एक सत बुलेटिन, मुरैना

जिले में नागरिक सुरक्षा एवं आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने के उद्देश्य से 26 नवम्बर 2026 को सिविल डिफेंस मॉक अभ्यास आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ ने इस संबंध में जिले के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय, महानिदेशालय अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक, नई दिल्ली के निर्देशों तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पत्र के क्रम में जिले में सिविल डिफेंस हवाई हमले एवं ब्लैकआउट से संबंधित द्वितीय मॉक ड्रिल आयोजित की जानी है। मॉक अभ्यास के दौरान हवाई हमले की चेतावनी, ब्लैकआउट संबंधी उपाय, सुरक्षित स्थानों पर निकासी, खोज एवं बचाव कार्य तथा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया की व्यवस्थाओं का अनुकरण किया जाएगा। कलेक्टर ने जिला कमांडेंट, होमगार्ड मुरैना को इस संपूर्ण अभ्यास के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि अभ्यास में सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों, होमगार्ड, एनसीसी कैडेट्स एवं अन्य हितधारकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। साथ ही संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ आवश्यक तैयारियां पूर्ण करें, ताकि निर्धारित तिथि 26 नवम्बर को मॉक अभ्यास का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा सके। मॉक अभ्यास के सफल आयोजन के लिए पुलिस अधीक्षक, संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक समन्वय एवं व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

भिण्ड में अब दो पालियों में चलेंगे ई-रिक्शा: 300 की कलर कोडिंग पूरी, शेष की अभियान मोड पर 2-3 दिनों में होगी



एक सत बुलेटिन, भिण्ड

शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारु और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने सक्रिय अभियान शुरू किया है। कलेक्टर श्री पवन जैन की अध्यक्षता में हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जिला परिवहन अधिकारी श्री राजेन्द्र सोनी के नेतृत्व में विभागीय दल ने जिले में संचालित अन्य राज्यों में पंजीकृत रिक्शों पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में अवैध रूप से चल रहे रिक्शे जप्त किए गए हैं। जिन पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अन्य राज्यों में पंजीकृत या बिना नंबर प्लेट वाले जितने भी रिक्शे या ई रिक्शा (टमटम) जिले में संचालित हो रहे हैं, उन्हें जप्त कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उद्देश्य है कि सड़कों पर केवल वैध दस्तावेजों और नियमों के अनुसार संचालित वाहन ही रहें, जिससे यातायात जाम और दुर्घटनाओं की संभावना घटे।सड़क सुरक्षा समिति के निर्णय के अनुसार नंबर प्लेट लगे रजिस्टर्ड ई-रिक्शों की कलर कोडिंग की जा रही है। इसके तहत ई-रिक्शे शहर में दो पालियों में संचालित होंगे, ताकि सड़कों पर वाहनों का दबाव कम हो और यातायात व्यवस्था बेहतर हो सके। अब तक 300 ई-रिक्शों की कलर कोडिंग पूरी की जा चुकी है।

अभियान मोड में तैयारी

शेष सभी रजिस्टर्ड ई-रिक्शों की कलर कोडिंग अभियान मोड में दो से तीन दिनों में पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद सभी वाहन निर्धारित नियमों के अनुसार अपनी-अपनी पाली में संचालित होंगे। प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से यात्रियों को व्यवस्थित परिवहन मिलेगा और शहर की सड़कों पर सुरक्षा बढ़ेगी। कलेक्टर श्री पवन जैन के निर्देशन में प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे ये ठोस कदम भिण्ड शहर को जाममुक्त, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।परिवहन विभाग की सख्ती से उन रिक्शा संचालकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जो आवश्यक दस्तावेजों और वैध अनुमति के बिना वाहन चला रहे हैं। विभाग की कार्रवाई के तहत वाहनों के जरूरी दस्तावेजों और संचालन संबंधी नियमों की जांच की जा सकती है। शहर में यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाहनों का नियमानुसार संचालन जरूरी है। ऐसे में परिवहन विभाग की यह पहल नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों के लिए चेतावनी मानी जा रही है।

वन सुरक्षा पखवाड़े में वन भूमि पर अतिक्रमण का प्रयास विफल

मुरैना। वन सुरक्षा पखवाड़े के तहत वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त रखने एवं वन संपदा के संरक्षण के लिए वन विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मुख्य वन संरक्षक, ग्वालियर के निर्देशन एवं वनमंडलाधिकारी, मुरैना के मार्गदर्शन में वन विभाग की संयुक्त टीम ने पहाड़गढ़ वन परिक्षेत्र में अतिक्रमण के प्रयास को विफल करते हुए लगभग 20 हेक्टेयर वन भूमि को सुरक्षित कराया। वन परिक्षेत्र पहाड़गढ़ के बीट कन्हार स्थित वन कक्ष क्रमांक पी-224 में कुछ व्यक्तियों द्वारा लगभग 20 हेक्टेयर वन भूमि की कटाई-सफाई कर उसे कृषि भूमि में परिवर्तित करने तथा फसल उत्पादन के उद्देश्य से जुताई किए जाने का मामला सामने आया था। संबंधित व्यक्तियों ने वन भूमि पर अवैध कब्जे की मंशा से क्षेत्र के चारों ओर बाड़ भी लगा दी थी। सूचना मिलने पर उपवनमंडलाधिकारी, सबलगढ़ एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी, पहाड़गढ़ के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर प्रभावी कार्रवाई की। टीम द्वारा जेसीबी मशीन से वन भूमि में खंतियां खुदवाई गईं तथा लोडर मशीन की सहायता से अतिक्रमण के प्रयास को विफल किया गया। साथ ही वन भूमि के चारों ओर लगाई गई बाड़ को भी हटाया गया, जिससे भविष्य में पुनः अतिक्रमण की संभावना को रोका जा सके। कार्रवाई कर लगभग 12 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था।

युवा उत्सव में विद्यार्थियों ने दिखाई संगीत प्रतिभा परकशन एवं नॉन-परकशन में हुए मुकाबले

एक सत बुलेटिन, मुरैना

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार जिला स्तरीय युवा उत्सव 2026-27 के अंतर्गत शास्त्रीय एकल वादन (परकशन एवं नॉन-परकशन) प्रतियोगिताओं का आयोजन शासकीय महाविद्यालय बानमोर में किया गया। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता कर अपनी संगीत प्रतिभा एवं वादन कौशल का प्रदर्शन किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एस.के. किरार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. धर्मेंद्र सिंह धाकड़ ने की। प्राचार्य डॉ. किरार ने कहा कि युवा उत्सव विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने, आत्मविश्वास बढ़ाने तथा भारतीय कला एवं सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। युवा उत्सव प्रभारी डॉ. ज्योति ने प्रतियोगिताओं का समन्वय एवं संचालन किया। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत के महत्व पर



प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को कला के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने ताल, लय एवं वाद्य कौशल का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। निर्णायक मंडल द्वारा प्रस्तुतियों का मूल्यांकन कर परिणाम घोषित किए गए। शास्त्रीय एकल वादन (परकशन) प्रतियोगिता में पी.जी. कॉलेज मुरैना के सत्यम चौहान ने प्रथम तथा पी.जी. कॉलेज अंबाह की निधि कुशवाह ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं शास्त्रीय एकल वादन (नॉन-परकशन) प्रतियोगिता में पी.जी. कॉलेज अंबाह की निधि कुशवाह प्रथम तथा पी.जी. कॉलेज मुरैना की चंद्रकांता द्वितीय स्थान पर रहीं। प्रतियोगिता के निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए निर्णायक मंडल में डॉ. भरत सोनी, सहायक प्राध्यापक, पी.जी. कॉलेज मुरैना, डॉ. शिवचरण, ग्रंथपाल, शासकीय महाविद्यालय कैलारस तथा डॉ. अनूप कुमार, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय बानमोर शामिल रहे। इस अवसर पर पी.जी. कॉलेज मुरैना से डॉ. ज्ञान सिंह उचाड़िया एवं डॉ. रेखा यादव भी अपने प्रतिभागियों के साथ उपस्थित रहे। आयोजन को सफल बनाने में महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉ. ऋचा गुप्ता, श्री दुर्गा शंकर लोधी, श्री धर्मेंद्र धाकड़, डॉ. सना खान, डॉ. शिवम परमार, श्री संजीव कुमार, डॉ. गायत्री राणा, डॉ. भावना बर्मन एवं डॉ. लक्ष्मी राजपूत का सराहनीय सहयोग रहा। अंत में विजेता प्रतिभागियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं तथा आयोजन में सहयोग देने वाले सभी प्राध्यापकों, निर्णायकों एवं सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

भिण्ड में यातायात सुधार के लिए 15 दिन का अभियान: अनाधिकृत वाहनों की जप्ती व राजसात की कार्रवाई

एक सत बुलेटिन, भिण्ड

भिण्ड जिले में कलेक्टर श्री पवन जैन के निर्देशानुसार जिला परिवहन विभाग आगामी 15 दिनों में यातायात सुधार एवं वाहन नियमों के अनुपालन हेतु विशेष अभियान चलाएगा। अभियान का उद्देश्य सड़कों पर बिना वैध परमिट, फिटनेस अथवा अनाधिकृत रूप से संचालित हो रहे वाहनों की पहचान कर उन्हें नियमों के अधीन लाना है। अभियान का उद्देश्य यह कार्यवाही यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और वैध वाहन संचालकों को न्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा देने के लिए की जा रही है। कलेक्टर ने



हाल में यातायात सुधार समिति की बैठक में स्पष्ट कहा था कि केवल आवश्यक दस्तावेज पूरे करने वाले वाहन ही संचालित होंगे। कार्रवाई का दायरा अभियान में बिना परमिट चल रहे वाहन, फिटनेस अवधि समाप्त हो चुके वाहन तथा अनाधिकृत रूप से संचालित वाहनों की विशेष जांच की जाएगी। नियम तोड़ने वाले वाहनों की जप्ती, राजसात की कार्यवाही एवं नियमानुसार अन्य कार्रवाई की जाएगी। वाहन को जप्त करने के साथ ही परमिट वाहनों पर टैक्सेशन संबंधी आवश्यक कार्यवाही भी की जाएगी। विभाग ने वाहन संचालकों को आवश्यक दस्तावेज पूरे करने की चेतावनी दी है, ताकि सड़क पर सुरक्षित एवं व्यवस्थित परिवहन सुनिश्चित हो सके।

वाहन संचालकों को सलाह

वाहन मालिकों एवं चालकों को समय रहते पंजीयन, फिटनेस, बीमा, परमिट एवं ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज पूरे कर लेने चाहिए। यह अभियान भिण्ड जिले में सुरक्षित यातायात, व्यवस्थित परिवहन एवं जनसुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

बसों में यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री को अनिवार्य रूप से निर्धारित दर का वैध टिकट जारी करना सुनिश्चित करें : जिला परिवहन अधिकारी

एक सत बुलेटिन, भिण्ड

जिला परिवहन अधिकारी भिण्ड ने भिण्ड जिले के समस्त यात्री बस संचालकों को पत्र जारी कर कहा है कि कलेक्टर भिण्ड को निरंतर यह शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि भिण्ड से ग्वालियर मार्ग पर संचालित होने वाली यात्री बसों के परिचालकों/संचालकों द्वारा यात्रियों को यात्रा टिकट जारी नहीं किए जा रहे हैं तथा यात्रियों से मनमाने तरीके से अधिक किराया वसूल किया जा रहा है। यह कृत्य मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों एवं परमिट की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः जिले के समस्त यात्री बस संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि अपनी बसों में यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री को अनिवार्य रूप से निर्धारित दर का वैध टिकट जारी करना सुनिश्चित करें। भविष्य में इस संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्त होने या आकस्मिक जांच में अनियमितता पाए जाने की दशा में संबंधित बस का परमिट निलंबित/निरस्त करने हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आरटीए), चम्बल संभाग मुरैना एवं ग्वालियर संभाग ग्वालियर को अनुशंसा (प्रतिवेदन) भेजी जाएगी तथा मोटरयान अधिनियम, 1988 की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार, विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया

चैक से संबंधित मामलों के निराकरण के लिये आयोजित विशेष लोक अदालत में हुआ निराकरण

एक सत बुलेटिन, भिण्ड

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार दिनांक 21 नवम्बर 2026 को संपूर्ण भिण्ड जिले में धारा 138 एनआईएक्ट अंतर्गत् चैक के अनादरण से संबंधित मामलों के राजीनामा के माध्यम से निराकरण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। श्री के.एस. बारिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय भिण्ड के निर्देशन में एवं श्री उपदेश राठौर, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय भिण्ड एवं न्यायिक तहसील मेहगांव, गोहद, एवं लहार न्यायालय में दिनांक 21 नवम्बर 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष के आदेशानुसार विशेष लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण किये जाने हेतु जिला मुख्यालय भिण्ड में 02 खण्डपीठ, न्यायिक तहसील मेहगांव में 02 खण्डपीठ, लहार में 01 खण्डपीठ एवं गोहद में 02 खण्डपीठों का गठन किया गया। इस प्रकार से जिले में कुल 07 खण्डपीठों का गठन किया गया था। इस विशेष लोक अदालत में परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत चैक के अनादरण के संबंध में न्यायालयों में लंबित 16 प्रकरणों का निराकरण किया गया गया, जिनमें समझौता राशि रूपये 60,38,121/- रही। जिनमें समझौता राशि रूपये 60,38,121/- रही। जिला न्यायालय भिण्ड म.प्र. में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड की



खण्डपीठ क्रमांक 02 के समक्ष आज दिनांक 21 नवम्बर 2026 को न्यायालय में लंबित प्रकरण को राजीनामा के माध्यम से पक्षकारों की आपसी सहमति से निराकृत किया गया। दिनांक 08-09-2020 से न्यायालय में लंबित उपरोक्त प्रकरण क्रमांक-06/2021 में मेघनाथ सिंह विरूद्ध शैलेन्द्र सिंह अंतर्गत धारा-138 एस.सी.एन.आई.ए. (परक्राम्य लिखत अधिनियम) में दिनांक 21-11-2026 को आयोजित विशेष लोक अदालत में दोनों पक्षों के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया। प्रकरण में विवादित चैक राशि 15,00,000/- रूपये से प्रकरण में उपस्थित पक्षकार को लाभान्वित किया गया। उभयपक्ष के मध्य कोई विवाद शेष नहीं होने से प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की गई।

संपादकीय

आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं

आत्महत्या की प्रवृति होना आधुनिकता और भौतिकवाद का प्रभाव भी है। यह बढ़ते नशीले पदार्थों का प्रतिबिम्ब भी है। बच्चे तनाव और दबाव में हैं, माता-पिता और अभिभावकों के पास उनके लिए समयाभाव है। आज बच्चे अकेलेपन का शिकार हैं। उनके पास कोई साथी और सहारा नहीं है। मानवीय जीवन सभी प्रकार के लौकिक और अलौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए है। भारतीय शास्त्रों और पुराणों में मनुष्य जीवन सभी योनियों से श्रेष्ठ है। यह परमात्मा द्वारा दिया गया एक पवित्र और दुर्लभ अवसर है जिसका उद्देश्य अपने कर्मों को सुधारना तथा आत्मिक चेतना का विकास करना है। शास्त्रों के अनुसार देवताओं को भी इस बात की इच्छा रहती है कि वे मनुष्य शरीर प्राप्त कर सत्कर्म करें और जीवन सफल बनाएं। इसी उद्देश्य से भगवान राम और भगवान कृष्ण मनुष्य देह में जन्म लेकर लोगों के कल्याणार्थ मनुष्य की योनी में धरती पर आए। त्रेता युग में भगवान राम का जन्म एक साधारण मनुष्य की तरह हुआ। भगवान राम ने सिखाया कि परिवार, समाज तथा राज्य की मयार्दा में नियमों का पालन कैसे किया जा सकता है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य न खोना, मर्यादित आचरण, मानव जीवन को जीने की कला सीखना तथा सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना राम तत्व का सार है। इसी प्रकार द्वापर युग में फल की चिंता किए बिना अपना कर्म पूरी निष्ठा से करना, जीवन में हर चुनौती के बीच मुस्कुराते रहना, निर्भय होना, निःस्वार्थ प्रेम तथा भक्ति कृष्ण तत्व का सार है। दोनों ने ही सत्य, प्रेम, शांति और धमार्नुसार जीवन को जीने का संदेश दिया। मनुष्य को अपने जीवन का महत्व समझते हुए सुख, शान्ति, प्रेम और आदर, श्रद्धा और विश्वास से जीवनयापन करना चाहिए। बहुत ही दुःखद है कि अनेकों बार मनुष्य अपने दुःख-दर्द, कष्टों, परेशानियों और तकलीफों को पहाड़ समझ बैठता है और आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है। उसे लगता कि इस दुनिया में कोई उसका नहीं है और विभिन्न पारिवारिक, सामाजिक, शारीरिक और मानसिक कारणों की वजह से वह क्षण भर में आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठा लेता है।

अत्यधिक नशीले पदार्थों के सेवन से विवेक मर जाना भी इसका एक प्रमुख कारण है। आत्महत्या अत्यधिक मानसिक पीड़ा और निराशा से उपजी एक अवस्था है जो क्षण भर में घटित हो जाती है। चिंतनीय यह भी है कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति अबोध बच्चे हैं जिन्हें जीवन का कुछ पता ही नहीं, युवा भी हैं और अधेड़ उम्र के वृद्ध भी हैं। असफल ही नहीं, धनवान और सफल व्यक्ति भी हैं। जो यह जानते कि आत्महत्या के पश्चात कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्षण भर में आवेश में आकर ऐसा दुस्साहसी कदम उठा लेते हैं। वास्तव में आत्महत्या कोई साहसी कदम नहीं है। यह एक कायर और डरपोक व्यक्ति का काम है जो दुनिया के कष्टों, तकलीफों और परेशानियों से सामना न करके मौत को गले लगा लेता है। वर्तमान में व्यक्ति में सहन करने की क्षमता बहुत कम हो गई है। छोटी सी बात का बहाना, प्रेम सम्बन्ध में असफलता, पारिवारिक विवाद, वैवाहिक जीवन में तनाव, बाहरी घटनाओं का दबाव, मन इच्छित न मिल पाना, परीक्षा में असफलता, बैंक का कर्ज, पारिवारिक झगड़ा, मानसिक तनाव, जिद, आक्रोश, खौफ, अकेलापन, परेशानी, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, चिंता, आत्मसंयम खो देना या किसी चुनौती का सामना न कर पाना ही आत्महत्या का मुख्य कारण रहता है। इसके अतिरिक्त अनेक व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी कारण भी ऐसी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में रहते हैं। इस सन्दर्भ में पन्द्रह नवंबर रविवार की शाम को छह बजे के करीब जिला बिलासपुर के घुमारवीं शहर के साथ लगते सीर खड्ड पुल पर चौदह-पंद्रह वर्ष की दो नाबालिग लड़कियों का छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक है।

आत्महत्या के क्या कारण रहे होंगे, यह पुलिस की जांच-पड़ताल का विषय है, लेकिन अबोध बालिकाओं का क्षणभर में अपनी जीवनलीला समाप्त कर लेना परिवार, समाज तथा मानवता पर एक बड़ा प्रश्नचिन्ह है। जिन बच्चों ने अभी जीवन देखा नहीं, कोई अच्छे-बुरे की समझ नहीं, उन्होंने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया होगा?

नई तकनीक तैयार करके आगे बढ़ता भारत

डा. जयंतीलाल भंडारी

> फिनटेक, एड-टेक, हेल्थ-टेक और एग्री-टेक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय स्टार्टअप्स न केवल क्रांतिकारी तकनीकी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर नए रोजगार सृजित कर भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी एफडीआई भी आकर्षित कर रहे हैं। इसके साथ ही डिजिटल वाणिज्य के लिए खुला नेटवर्क (ओएनडीसी) जैसी दूरदर्शी पहलों ने ई-कॉमर्स क्षेत्र में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एकाधिकार को सीधी चुनौती दी है।

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन (ईएसटीआईसी) को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ वर्षों पहले तक देश के बाहर ईजाद हुई तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत अब नए डिजिटल दौर में स्वयं नई आधुनिक तकनीक तैयार करके नई सोच और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को न केवल भविष्य की तकनीकों को अपनाना चाहिए, बल्कि साहसिक प्रयोग और नवाचार करते हुए भविष्य की तकनीक के विकास के लिए दुनिया का नेतृत्व भी करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से बढ़ते साइबर सुरक्षा के खतरों पर चिंता जताई और कहा कि वित्तीय नेटवर्क और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए मजबूत समाधान विकसित करने होंगे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित जटनी में भारतीय रिजर्व बैंक के डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह नया सेंटर पूरे देश को एक सुरक्षित, आधुनिक और आत्मनिर्भर डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इससे देश की तेजी से बढ़ती डिजिटल बैंकिंग, भुगतान (यूपीआई) और अंतर-बैंकिंग निपटान प्रणालियों को तकनीकी रूप से नया सुदृढ़ आधार मिलेगा।

मोदी ने कहा कि डिजिटल सेवाओं के समावेश से चौबीसों घंटे पारदर्शी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हुई है। पहले जहां औपचारिक बैंकिंग प्रणाली तक छोटे कारोबारियों की पहुंच असंभव मानी जाती थी, वहीं आज बिना किसी संपत्ति की गारंटी के रेहड़ी-पटरी वालों, पारंपरिक कारीगरों, छोटे उद्यमियों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आसान एवं सस्ता संस्थागत ऋण प्राप्त हो रहा है। डिजिटल पहचान और आधुनिक तकनीकी ढांचे ने देश के सबसे निर्धन वर्ग को वित्तीय रूप से मुख्यधारा में शामिल किया है। गौरतलब है कि केयरएज ग्लोबल रेटिंग्स की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तंत्र दुनिया के 10 सबसे असरदार संरचनात्मक सुधारों में शामिल हो चुका है।

वैश्विक स्तर पर 38 देशों के 43 प्रमुख सुधारों का गहन अध्ययन करने के बाद जारी की गई इस वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के इस अभूतपूर्व डिजिटल ढांचे ने न केवल आम नागरिकों के लिए प्रशासनिक और बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाया है, बल्कि लेन-देन की लागत में भी ऐतिहासिक कटौती की है। इसी तरह स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी (साइड) 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत अब विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था बन गया है। इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट रूप से उजागर होता है कि भारत ने अपनी डिजिटल कार्यक्षमता, नेटवर्क कवरेज और तकनीकी प्रदर्शन में जर्मनी, फ्रांस, जापान और कनाडा जैसे कई विकसित राष्ट्रों को पीछे छोड़ दिया है। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि भारत का डिजिटल विकास देश की आर्थिक प्रगति का नया आधार बन गया है। बीते एक दशक में भारत ने जिस तीव्र गति, दूरदर्शिता और नवाचार के साथ अपने डिजिटल तंत्र का विस्तार किया है, उसने देश के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य को पूरी तरह बदलकर रख दिया है। डिजिटल इंडिया अभियान से आरंभ हुई यह यात्रा आज दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सफल डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण तक पहुंच चुकी है। इस अभूतपूर्व डिजिटल अभियान की मजबूत रीढ़ ह्यइंडिया स्टैकह्न है, तीन प्रमुख और परस्पर जुड़े स्तंभों- आधार, यूपीआई तथा डिजीलॉकर एवं अकाउंट एग्रीगेटर पर टिका हुआ है।

इस तकनीकी रीढ़ को जमीनी स्तर पर मजबूती देने में जैम ट्रिनिटी (जन धन, आधार और मोबाइल) की भूमिका ऐतिहासिक रही है। इसने देश के करोड़ों असंगठित, निर्धन और वंचित नागरिकों को सीधे मुख्यधारा की औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है। सस्ते हाई-स्पीड इंटरनेट डेटा, 5 जी नेटवर्क के तीव्र प्रसार और किफायती स्मार्टफोन की व्यापक उपलब्धता ने इस डिजिटल ढांचे को देश के अंतिम गांव तक पहुंचा दिया है। निश्चित रूप से भारत की डिजिटल प्रणाली की सफलता का मूल कारण विभिन्न सरकारी संस्थानों, नियामकों (रेगुलेटर्स), बैंकों और तकनीकी संस्थाओं के बीच का बेहतर तालमेल और रणनीतिक सहयोग रहा है। भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे की सफलता का सबसे व्यापक और सकारात्मक प्रभाव सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र तथा छोटे व्यापारियों पर देखा गया है। आज देश में 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते संचालित हैं। इन जीरो बैलेंस खातों के माध्यम से सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) राशि बिना किसी बिचौलिए के सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित हो रही है। सूक्ष्म और छोटे उद्यमों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चलाई गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक 60 करोड़ से अधिक बिना गारंटी वाले ऋण खातों के लिए 43 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विशाल राशि स्वीकृत की जा चुकी है। डिजिटल लेन-देन के क्षेत्र में भारत ने विश्व स्तर पर अपना वर्चस्व स्थापित किया है।

वर्ष 2016-17 के बाद से यूपीआई के वार्षिक लेन-देन की संख्या में लगभग 13000 गुना की आश्चर्यजनक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्तमान में यूपीआई के माध्यम से औसतन प्रतिदिन लगभग 80 करोड़ लेन-देन हो रहे हैं। भारत आज दुनिया के कुल रियल-टाइम डिजिटल भुगतान के लगभग आधे हिस्से का अकेले नेतृत्व करता है। एक छोटे चाय या सब्जी विक्रेता से लेकर बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों तक, डिजिटल लेन-देन के व्यापक प्रसार ने नकद प्रबंधन की भारी लागतों को समाप्त कर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता को अभूतपूर्व गति प्रदान की है। इससे व्यापार में पारदर्शिता बढ़ी है और देश का कर आधार व्यापक हुआ है। सस्ते इंटरनेट और मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने देश में उपभोक्ता व्यवहार को एक नई परिभाषा देते हुए भारत को विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना दिया है।

नागरिक मेटा का यूजर है, गुलाम नहीं!

डिजिटल लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी और कॉरपोरेट सत्ता का बढ़ता नियंत्रण

भूपेंद्र गुप्ता



लोकतंत्र में नागरिक किसी सरकार का अधीनस्थ नहीं होता, वह संविधान का अधिकार-संपन्न नागरिक होता है। यही बात डिजिटल दुनिया पर भी लागू होनी चाहिए। आम नागरिक फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप का उपयोगकर्ता है, उनका अधीनस्थ नहीं। वह इन प्लेटफॉर्मों पर अपने विचार व्यक्त करता है, सूचनाओं का आदान-प्रदान करता है, राजनीतिक बहस करता है और सत्ता से सवाल पूछता है। लेकिन जब उसकी अभिव्यक्ति की सीमाएं तय करने का अधिकार कुछ निजी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में केंद्रित होने लगता है, तब यह केवल तकनीकी या व्यावसायिक विषय नहीं रह जाता, बल्कि लोकतंत्र के भविष्य का प्रश्न बन जाता है।

मेटा जैसी कंपनियां आज केवल सोशल मीडिया सेवाएं उपलब्ध नहीं करा रहीं। वे आधुनिक समाज में जनमत निर्माण, राजनीतिक संवाद और सार्वजनिक विमर्श की महत्वपूर्ण संरचना बन चुकी हैं। किसकी पोस्ट कितने लोगों तक पहुंचेगी, किसकी सामग्री हटाई जाएगी, किसका अकाउंट प्रतिबंधित होगा और किसकी आवाज एल्गोरिदम के माध्यम से दब जाएगी—इन सब पर इन कंपनियों की नीतियों का सीधा प्रभाव पड़ता है। यह शक्ति किसी निर्वाचित संस्था के पास भी नहीं है। सवाल यह है कि इतनी व्यापक सामाजिक शक्ति के इस्तेमाल पर जवाबदेही किसकी है?

युवक कांग्रेस के नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट प्रतिबंधित किए जाने के बाद मेटा के कार्यालयों पर हुए प्रदर्शन ने इसी बहस को राष्ट्रीय स्तर पर ला खड़ा किया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की आलोचना करने वाली आवाजों के विरुद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चुनिंदा ढंग से कार्रवाई कर रहे हैं। यदि यह आरोप सही है तो यह अत्यंत गंभीर मामला है। यदि किसी राजनीतिक दल के नेताओं की सामग्री केवल इसलिए हटाई जाती है कि वे सरकार की आलोचना करते हैं, तो यह डिजिटल माध्यमों के जरिए लोकतांत्रिक असहमति को सीमित करने जैसा होगा।

हालांकि इस आरोप की स्वतंत्र जांच और तथ्यों की पुष्टि आवश्यक है। किसी अकाउंट पर प्रतिबंध लगने मात्र से राजनीतिक भेदभाव सिद्ध नहीं होता। मेटा को स्पष्ट करना चाहिए कि कार्रवाई किस नियम के तहत हुई, किसकी शिकायत पर हुई और उसके विरुद्ध अपील की क्या व्यवस्था उपलब्ध है।

यहां एक दूसरा और अधिक बुनियादी सवाल भी है। क्या मेटा को यह अधिकार है कि वह करोड़ों नागरिकों के सार्वजनिक संवाद का निर्णायक बन जाए? निश्चित रूप से किसी निजी कंपनी को अपनी सेवाओं के संचालन और अनुचित सामग्री पर नियंत्रण का अधिकार है। लेकिन जब उसका प्लेटफॉर्म लोकतांत्रिक संवाद का प्रमुख माध्यम बन जाता है, तब उसकी जिम्मेदारी भी केवल व्यावसायिक शर्तों तक सीमित नहीं रह सकती। पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही उसकी अनिवार्य जिम्मेदारियां होनी चाहिए।

भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1)(ं) के अंतर्गत नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। यह अधिकार मुख्यतः राज्य के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई निजी प्लेटफॉर्म हर प्रकार की सामग्री प्रकाशित करने के लिए बाध्य है। लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं कि निजी कंपनियों की नीतियों और सरकारी निदेर्शों के जरिए नागरिकों की आवाज को मनमाने ढंग से दबाने की व्यवस्था स्वीकार कर ली जाए। सरकार और कंपनियों, दोनों के निर्णय कानून, पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया की कसौटी पर परखे जाने चाहिए।

भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर सरकारी नियंत्रण और सामग्री हटाने के निदेर्शों को लेकर पहले से ही गंभीर बहस चल रही है। यदि सरकार किसी सामग्री को हटाने का निर्देश देती है तो नागरिकों को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि उसका कानूनी आधार क्या है। यदि मेटा अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस के आधार पर सामग्री हटाती है तो उसे भी समान नियमों का पालन करना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों के लिए एक ही कसौटी होनी चाहिए।

उदाहरण के तौर पर राहुल गांधी की एक तस्वीर जिसमें वे तिरंगा हाथ में लिये हैं कोई कमेंट नहीं लिखा ,उसे भारत में प्रदर्शन के लिये प्रतिबंधित किया गया मेरी ही प्रोफाईल पर ।क्या मेटा इसकी कानूनी बाध्यता समझा सकती है ।क्या मेटा यह स्पष्ट करेगी कि राहुल गांधी की तस्वीर और वीडियो को प्रतिबंधित करने का वास्तविक कानूनी आधार क्या था? क्या किसी सरकारी एजेंसी का निर्देश था या कंपनी के एल्गोरिदम ने स्वयं ऐसा निर्णय लिया? यदि यह तकनीकी गलती थी तो क्या ऐसी गलतियों से प्रभावित प्रत्येक नागरिक को समान रूप से न्याय और स्पष्टीकरण मिलता है? सवाल राहुल गांधी की तस्वीर का नहीं, उस व्यवस्था का है जिसमें किसी नागरिक की आवाज बिना पारदर्शी कारण के डिजिटल मंच से गायब हो सकती है ।क्या तामिलनाडु के मुख्यमंत्री के इंस्टाग्राम अकाउंट , प्रधानमंत्री का वीडियो या अदालत की कार्यवाही के विडियो गायब होना केवल तकनीकि त्रुटि का हिस्सा हैं ?यह जबाब तो आना ही चाहिये।

लेकिन इस आंदोलन के संदर्भ में युवक कांग्रेस के प्रदर्शन के तरीके पर भी विचार करना आवश्यक है। किसी कंपनी की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन कार्यालय परिसर में घुसकर तोड़फोड़ करना या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। इससे मूल मुद्दे की गंभीरता कम होती है और आंदोलन को राजनीतिक रूप से कमजोर करने का अवसर विरोधियों को मिलता है। कांग्रेस का ऐतिहासिक आधार सत्याग्रह, शांतिपूर्ण प्रतिरोध और लोकतांत्रिक संघर्ष रहा है। उसे अपनी लड़ाई भी इन्हीं मूल्यों के आधार पर लड़नी चाहिए।

इस आंदोलन को केवल उदय भानु चिब या किसी अन्य नेता के अकाउंट बहाल कराने की मांग तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यह करोड़ों भारतीयों की डिजिटल स्वतंत्रता का आंदोलन बनना चाहिए। मेटा से पूछा जाना चाहिए कि पिछले वर्षों में भारत सरकार के निदेर्शों पर कितने अकाउंट और पोस्ट प्रतिबंधित किए गए? कितने मामलों में कंपनी ने स्वतंत्र रूप से कार्रवाई की? क्या राजनीतिक सामग्री के मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए समान मानदंड अपनाए गए? कितने लोगों को अपने अकाउंट प्रतिबंधित होने के विरुद्ध प्रभावी अपील का अवसर मिला?

यह भी जरूरी है कि डिजिटल कंपनियों की नीतियों का स्वतंत्र ऑडिट हो और सरकारी निदेर्शों का सार्वजनिक विवरण उपलब्ध कराया जाए। संसद को भी इस विषय पर गंभीर चर्चा करनी चाहिए। नागरिकों के डिजिटल अधिकारों की रक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था बने जिसमें न सरकार मनमानी कर सके और न कोई निजी कंपनी।

दरअसल, डिजिटल युग में लोकतंत्र की नई चुनौती यही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल कागज पर सुरक्षित न रहे। आज किसी नागरिक की आवाज को दबाने के लिए अखबार बंद करना या सभा रोकना ही पर्याप्त नहीं है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट की पहुंच सीमित करना, पोस्ट हटाना या अकाउंट प्रतिबंधित करना भी उसके सार्वजनिक संवाद को प्रभावित कर सकता है।

लोकतंत्र में असहमति कोई अपराध नहीं है। सरकार की आलोचना राष्ट्रविरोध नहीं है और सवाल पूछना किसी कंपनी की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता, जब तक कि वह निर्धारित कानूनी और उचित सीमाओं में हो। इसलिए मेटा के सामने सवाल केवल युवक कांग्रेस का नहीं, भारत के प्रत्येक सोशल मीडिया उपयोगकर्ता का है। नागरिक मेटा का यूजर है, उसकी संपत्ति नहीं। वह प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है, उसके अधीन जीवन नहीं जीता। उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी कॉरपोरेट कंपनी की कृपा पर निर्भर नहीं हो सकती। डिजिटल लोकतंत्र में कंपनियां सेवा दे सकती हैं, नागरिकों की आवाज की मालिक नहीं बन सकतीं। यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सबक और लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण मांग है।

(लेखक स्वतंत्र विश्लेषक हैं)

न्यूज ब्रीफ

अज्ञात वाहन की टक्कर से ट्रैक्टर चालक की मौत

ग्वालियर। डबरा थाना क्षेत्र स्थित सिंध नदी के पुल पर रात धान बेचकर ट्रैक्टर-ट्रॉली से घर लौट रहे एक किसान को अज्ञात वाहन चालक ने लापरवाही से अपना वाहन चलाते हुए पीछे से टक्कर मारी। हादसा इतना भीषण था कि किसान का एक पैर कटकर अलग हो गया और शरीर में कई जगह गंभीर चोटें आई। जिससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक का शव पीएम हाउस पहुंचाकर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। दतिया के ग्राम भदौना निवासी रवीन्द्र सिंह रावत (36) पुत्र नारायण सिंह रावत ट्रैक्टर-ट्रॉली में धान लेकर मंडी में बेचने गया था। धान बेचने के बाद वह रात में अपने गांव लौट रहा था। रात करीब 11:30 बजे सिंध नदी पुल से पहले पहुंचा, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आए अज्ञात वाहन ने उसके ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही रवीन्द्र सड़क पर गिर पड़ा। हादसे में उसका एक पैर कटकर अलग हो गया और शरीर में गंभीर चोटें आई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुर कर दी है।

दंदरौआ धाम में श्रीराम कथा एवं सामूहिक विवाह सम्मेलन 3 से

ग्वालियर। न्यू समर्पण सेवा समिति के तत्वावधान में तीन से 12 दिसंबर तक दंदरौआ धाम शताब्दीपुरम में श्रीराम कथा एवं सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें कथावाचक संत रमेश भाई शुक्ला के श्रीमुख से श्रद्धालु श्रीराम कथा का श्रवण करेंगे। समिति के अध्यक्ष नीलू भदौरिया ने बताया कि संस्था की ओर से पांचवीं बार श्रीराम कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा प्रतिदिन दोपहर एक बजे से शाम पांच बजे तक होगी। आयोजन के दौरान 10 दिसंबर को द्वितीय सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके माध्यम से जरूरतमंद जोड़ों के विवाह संपन्न कराए जाएंगे। आयोजन का समापन 12 दिसंबर को हवन, पूर्णाहुति और प्रसादी वितरण के साथ होगा। समिति की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अध्यक्ष नीलू भदौरिया ने श्रद्धालुओं और धर्मप्रेमी नागरिकों से कथा में शामिल होकर धर्मलाभ लेने की अपील की है।

प्रज्ञा प्रवाह के तत्वावधान में राष्ट्रीय समरसता समागम बैठक 24 को

ग्वालियर। प्रज्ञा प्रवाह के तत्वावधान में न हिंदू पतितो भवेत् की अवधारणा पर आधारित राष्ट्रीय समरसता समागम की तैयारियों को लेकर रविवार को गालव सभागार में बैठक आयोजित की गई। राष्ट्रीय समरसता समागम का आयोजन आगामी 24 नवंबर को जीवाजी विश्वविद्यालय के गालव सभागार में किया जाएगा। प्रज्ञा प्रवाह की प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि इस कार्यक्रम के निमित्त प्रज्ञा प्रवाह के प्रांत संयोजक धीरेन्द्र चतुर्वेदी के संयोजन में बैठक गालव सभागार में संपन्न हुई। जिसमें तैयारियों को लेकर विचार-विमर्श किया गया।

लेखा प्रशिक्षण परीक्षा के लिये ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी, 29 को होगी परीक्षा

ग्वालियर। ग्वालियर-चंबल संभाग में स्थित शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों में पदस्थ ऐसे शासकीय कर्मचारी जिन्होंने लेखा प्रशिक्षण शाला से नियमित प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उनकी विभागीय लेखा प्रशिक्षण परीक्षा नवम्बर 2026 भोपाल स्थित राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्याल में रविवार 29 नवम्बर को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक आयोजित होगी। लेखा प्रशिक्षण शाला के प्राचार्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी प्रशिक्षणार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। प्रवेश पत्र विभागीय पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं। प्रवेश पत्र पृथक से उपलब्ध नहीं कराए जायेंगे।

वार्ड 11 में शासकीय भूमि पर किए अवैध अतिक्रमण को हटाया

ग्वालियर। वार्ड 11 कबीर पार्क के सामने अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही निगम की भवन शाखा एवं मदाखलत अमले द्वारा की गई।
भवन निरीक्षक सुश्री तनुजा वर्मा ने बताया कि नगर निगम आयुक्त अभिषेक चौधरी के निर्देशानुसार वार्ड 11 कबीर पार्क के सामने भागीरथ कुशवाह द्वारा किये गये शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत मिलने पर भवन अधिकारी ब्रज किशोर त्यागी के निर्देशन में अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान मदाखलत अमला एवं पुलिस बल मौजूद रहा।

उद्योगों की जरूरत के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित करें, ताकि आसानी से मिले रोजगार : कलेक्टर चौहान



एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

जिले के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और उन्हें औद्योगिक क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप दक्ष बनाने के लिए कलेक्टर रुचिका चौहान ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिसकी वर्तमान समय में औद्योगिक इकाइयों और स्थानीय बाजार में मांग हो। इससे प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युवाओं को रोजगार हासिल करने में आसानी होगी और उद्योगों को भी अपनी आवश्यकता के अनुसार कुशल कर्मचारी मिल सकेंगे। कलेक्टर रुचिका चौहान सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला कौशल विकास समिति की मासिक बैठक को संबोधित कर रही थीं। बैठक में उन्होंने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आईटीआई) के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले की स्थानीय आवश्यकताओं, औद्योगिक इकाइयों की मांग और उपलब्ध रोजगार के अवसरों का अध्ययन कर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाएं। प्रशिक्षण का स्वरूप ऐसा होना चाहिए।

बहोड़ापुर चौराहे से सागरताल होते हुए दुर्गादास राठौर प्रतिमा तक बनेगी प्रमुख सड़क

15 करोड़ की सड़क सहित करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात, तोमर ने किया भूमिपूजन

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

उपनगर ग्वालियर के विकास को नई गति देने और क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने क्षेत्र में करोड़ों रुपये की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इस दौरान उन्होंने 15 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली प्रमुख सड़क निर्माण परियोजना का विधिवत भूमिपूजन कर कार्य की शुरुआत की। इस सड़क के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और लंबे समय से चली आ रही यातायात संबंधी समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है। यह प्रमुख सड़क बहोड़ापुर चौराहे से सागरताल होते हुए दुर्गादास राठौर प्रतिमा तक बनाई जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उपनगर ग्वालियर का चहुंमुखी विकास सरकार की प्राथमिकता है। क्षेत्र में सड़क, बिजली, शिक्षा और सीवर जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। विकास कार्यों को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आम नागरिकों को इनका वास्तविक लाभ मिल सके। विकास कार्यों से बदलेगी क्षेत्र की तस्वीर



ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि आज का कार्यक्रम केवल भूमिपूजन तक सीमित नहीं है, बल्कि उपनगर ग्वालियर के विकास में एक नए अध्याय की शुरुआत है। सड़क निर्माण सहित अन्य विकास कार्य पूरे होने से क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं में सुधार होगा। बेहतर सड़कें बनने से लोगों का आवागमन सुगम होगा और स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। सड़कों के निर्माण और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से आमजन के दैनिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।

ग्वालियर में स्थापित होंगे बड़े उद्योग, युवाओं को मिलेगा रोजगार

ऊर्जा मंत्री ने विकास कार्यों के साथ ग्वालियर में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अब ग्वालियर में बड़े-बड़े उद्योग स्थापित होने जा रहे हैं। इससे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। उन्होंने बताया कि विगत दिवस भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) के निवेशकों को आवंटन पत्र वितरित किए गए हैं। ग्वालियर के साडा क्षेत्र में करोड़ों रुपये की लागत से टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित किया जा रहा है। इस औद्योगिक परियोजना से लगभग 22 हजार लोगों को रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस परियोजना का सीधा लाभ ग्वालियर के नागरिकों को मिलेगा। औद्योगिक निवेश बढ़ने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर विकसित होंगे और क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी मजबूती मिलेगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उपनगर ग्वालियर में विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी है। एक ओर जहां सड़क, बिजली, सीवर और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है।

विश्व धरोहर सप्ताह के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित

प्रश्नोत्तरी के माध्यम से विद्यार्थियों ने जाना ऐतिहासिक-सांस्कृतिक विरासत का महत्व

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



विश्व धरोहर सप्ताह के तहत जिले में पुरातत्व धरोहरों पर केन्द्रित कार्यक्रम एवं गतिविधियां जारी हैं। इस क्रम में सोमवार को मोतीमहल में विद्यार्थियों के लिए विशेष धरोहर प्रश्नोत्तरी (क्विज़) प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यह प्रतियोगिता परिवहन न्यायालय के न्यायाधीश श्री शिवकांत के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुई। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में विद्यार्थियों से ग्वालियर एवं मध्यप्रदेश के ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों, भारतीय इतिहास, कला, संस्कृति एवं स्थापत्य कला से संबंधित प्रश्न पूछे गए। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए अपनी जानकारी एवं ज्ञान का प्रदर्शन किया। संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय के दिशा-निर्देशों के तहत यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। न्यायाधीश श्री शिवकांत ने इस अवसर पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरें हमारे गौरवशाली अतीत की जीवंत साक्षी हैं। इन धरोहरों में हमारी संस्कृति, परंपराओं, कला एवं स्थापत्य की अमूल्य विरासत समाहित है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को अपने इतिहास और विरासत से जुड़कर इनके संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति सजग और जिम्मेदार बनना चाहिए। साथ ही आह्वान किया कि अपनी विरासत के प्रति संवेदनशील बनें और ऐतिहासिक स्थलों को स्वच्छ व सुरक्षित रखने में सक्रिय भूमिका निभायें। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड, भोपाल से प्राप्त दिशा-निर्देशों के परिपालन में जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद द्वारा पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय के सहयोग से जिले के प्रमुख ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों पर विभिन्न जन-जागरूकता एवं पर्यटन संवर्धन गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

भूखे को भोजन कराना ही सबसे बड़ी सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा

ग्वालियर। हनुमान चौराहा हजारा भवन में आयोजित संगीतमय श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुप्रसिद्ध भागवताचार्य पूज्य पंडित घनश्याम शास्त्री जी महाराज ने अपनी मधुर वाणी से श्रीमद्भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन करते हुए श्रद्धालुओं को भक्ति, ज्ञान और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। महाराज श्री ने कथा के माध्यम से बताया कि श्रीमद्भागवत कथा केवल सुनने का विषय नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने और ईश्वर से जुड़ने का दिव्य माध्यम है। कथा के दौरान भजन-संकीर्तन और भक्तिमय प्रसंगों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। उपस्थित श्रद्धालु कथा अमृत का रसपान कर भावविभोर हो उठे। कथा के दौरान पूज्य महाराज श्री द्वारा संचालित अस्पताल में निशुल्क भोजन सेवा के सेवा कार्यों की भी चर्चा हुई। ग्वालियर में जरूरतमंद मरीजों एवं उनके अटेंडरों को प्रतिदिन निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

मेगा डस्ट क्लीनिंग अभियान के तहत गस्त का राम मंदिर रोड पर हुई विशेष सफाई

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



नगर निगम आयुक्त अभिषेक चौधरी के निर्देशन में शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार एवं धूल प्रदूषण की रोकथाम के लिए नगर निगम द्वारा मेगा डस्ट क्लीनिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत शहर के विभिन्न चिन्हित प्रमुख मार्गों पर विशेष सफाई एवं डस्ट क्लीनिंग का कार्य कराया जा रहा है।
मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि सोमवार को गस्त का ताजिया राम मंदिर रोड पर विशेष अभियान चलाकर सड़क एवं आसपास के क्षेत्रों में जमा धूल, मिट्टी तथा निर्माण सामग्री के अवशेषों को हटाया गया। साथ ही सड़क की सफाई कर धूल के जमाव को समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की गई। उल्लेखनीय है कि नगर निगम द्वारा 2 नवंबर से 2 दिसंबर 2026 तक प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 11 बजे तक मेगा ड्राइव फॉर माइक्रो डस्ट क्लीनिंग अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके तहत मुख्य मार्गों पर पेयजल छिड़काव एवं सफाई, निर्माण एवं विध्वंस से निकले मलबे का समुचित प्रबंधन, अतिक्रमण हटाने तथा सीवर एवं पेयजल से संबंधित समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा है।
नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जा रही है कि खुले में कचरा न फेंकें, कचरा न जलाएं तथा गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग रखें। साथ ही निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली रेत, गिट्टी एवं ईंट जैसी सामग्री सड़कों पर न फैलाएं, जिससे धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहयोग मिल सके।
नगर निगम का यह अभियान शहर को स्वच्छ, धूलमुक्त एवं प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में निरंतर जारी रहेगा।

धूल से राहत के लिए सागर ताल रोड सहित अन्य मुख्य मार्गों पर कराया पानी का छिडकाव

ग्वालियर। शहर में वायु प्रदूषण एवं धूल की समस्या पर नियंत्रण करने तथा नागरिकों को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगर निगम ग्वालियर द्वारा निरंतर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत शहर के प्रमुख मार्गों एवं व्यस्त क्षेत्रों में पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में फॉगिंग भी कराई जा रही है। नगर निगम आयुक्त अभिषेक चौधरी के निर्देषानुसार नगर निगम की टीम द्वारा प्रमुख सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव कर उड़ती धूल को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे राहगीरों, वाहन चालकों एवं आसपास रहने वाले नागरिकों को धूल से राहत मिल सके। वहीं फॉगिंग के माध्यम से मच्छरों की रोकथाम एवं नागरिकों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। नगर निगम द्वारा शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने और धूल प्रदूषण को कम करने के लिए यह अभियान निरंतर जारी है। जिसके तहत सागरताल रोड, आनंद नगर रोड सहित अन्य मुख्य मर्गों पर पर पानी का छिडकाव कराया गया। इसके साथ ही नगर निगम ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें।

ग्वालियर के डबरा-भितरवार में सुपर सीडर और हैप्पी सीडर से हो रहा पराली प्रबंधन

मध्यप्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं में कमी, श्योपुर-दतिया टॉप पर

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



खेतों में पराली जलाने से उठने वाले धुएं और बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर मध्यप्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से चिंता बनी हुई थी। खासतौर पर ग्वालियर क्षेत्र में पराली जलाने की घटनाओं के कारण उठने वाला धुआं दिल्ली तक पहुंचने की चर्चा हुई थी। इससे प्रदेश की किरकिरी भी हुई। इसके बाद सरकार और प्रशासन ने पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कई स्तरों पर प्रयास शुरू किए। किसानों को जागरूक करने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अब इन प्रयासों का असर आंकड़ों में दिखाई देने लगा है। इस वर्ष प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं में पिछले वर्षों की तुलना में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2022 में 21 नवंबर तक जहां पराली जलाने के 1477 मामले सामने आए थे, वहीं इस वर्ष इसी तारीख तक इनकी संख्या घटकर 558 रह गई है। हालांकि, प्रदेश के सभी जिलों में स्थिति एक जैसी नहीं है। कुछ जिलों में घटनाओं में कमी आई है, लेकिन श्योपुर और दतिया अब भी पराली जलाने के मामलों में सबसे आगे बने हुए हैं। वहीं ग्वालियर में डबरा और भितरवार क्षेत्र में पराली प्रबंधन के नए तरीके अपनाने और प्रशासनिक कार्रवाई के चलते सुधार देखने को मिला है। पिछले साल देश में सबसे ज्यादा थे पराली जलाने के मामले, इस साल आई बड़ी कमी सैटेलाइट तस्वीरों से सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2025 में 21 नवंबर तक मध्यप्रदेश में पराली जलाने के 11,925 मामले दर्ज किए गए थे। यह संख्या देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक थी। उस समय प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। हालांकि, इस वर्ष स्थिति में बदलाव आया है। 21 नवंबर 2026 तक प्रदेश में सैटेलाइट के माध्यम से पराली जलाने के 5,209 मामले दर्ज किए गए हैं।

श्योपुर में सबसे ज्यादा 953 मामले, दतिया में 899 घटनाएं दर्ज

प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आने के बावजूद कुछ जिले अब भी चिंता का विषय बने हुए हैं। श्योपुर इस मामले में लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। वर्ष 2025 में श्योपुर में पराली जलाने की 1,930 घटनाएं दर्ज की गई थीं। इस वर्ष भी 21 नवंबर तक यहां सबसे अधिक 953 मामले सामने आ चुके हैं। दतिया की स्थिति भी बहुत अलग नहीं है। पिछले साल यहां 1,185 घटनाएं दर्ज की गई थीं, जबकि इस वर्ष अब तक 899 मामले सामने आए हैं। यह प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। यानी दोनों जिलों में पिछले साल की तुलना में घटनाएं कम जरूर हुई हैं, लेकिन अन्य जिलों के मुकाबले यहां पराली जलाने का सिलसिला अधिक जारी है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि प्रदेश स्तर पर सुधार के बावजूद जिला स्तर पर रोकथाम के प्रयासों को और मजबूत करने की जरूरत है। खासकर श्योपुर और दतिया में किसानों को पराली के निस्तारण के वैकल्पिक तरीकों के प्रति जागरूक करना और खेतों में आग लगाने की घटनाओं पर निगरानी बढ़ाना जरूरी है।

6 करोड़ की परियोजना में कई महीनों से अटका निर्माण

एजी ऑफिस से विवेकानंद चौराहा तक 12 फीट चौड़ी होगी सड़क, इसी सप्ताह शुरू होगा काम

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात की समस्या से जूझ रहे वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है। एजी ऑफिस से विवेकानंद चौराहा तक सड़क चौड़ीकरण का काम इसी सप्ताह शुरू होने जा रहा है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के भोपाल स्थित मुख्यालय से इसके लिए सक्षम स्वीकृति मिल गई है। सड़क के बाई ओर करीब 12 फीट तक चौड़ीकरण किया जाएगा। खास बात यह है कि इस काम के लिए विभाग को अलग से बजट की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि व्हाइट टॉपिंग के काम में बची राशि का उपयोग किया जाएगा माधव नगर की ओर सड़क पर व्हाइट टॉपिंग नहीं की जाएगी, क्योंकि यह हिस्सा अभी नगर निगम के गारंटी पीरियड में है। ऐसे में इस हिस्से को व्हाइट टॉपिंग के एस्टीमेट से अलग रखा गया है। इससे बची राशि का इस्तेमाल सड़क की चौड़ाई बढ़ाने में किया जाएगा। चौड़ीकरण होने से इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही आसान होने की उम्मीद है। हालांकि, एजी ऑफिस पुल से नाका चंद्रवदनी होते हुए विक्की फैक्ट्री तक सड़क निर्माण का काम अभी भी पूरी तरह गति नहीं पकड़ पाया है। तकनीकी समस्याओं के चलते कई महीनों से निर्माण प्रभावित है। सड़क चौड़ीकरण की जरूरत व्हाइट टॉपिंग के निर्माण के दौरान सामने आई। दरअसल, पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन अधिकारियों ने सड़क का एस्टीमेट तैयार



करते समय कागजों में ही चौड़ाई का हिसाब तय कर लिया था। जब मौके पर निर्माण कार्य शुरू हुआ और वास्तविक स्थिति देखी गई, तब निर्धारित चौड़ाई के मुकाबले तीन से चार फीट तक जगह कम मिली। कई स्थानों पर यह अंतर छह फीट से भी अधिक पाया गया। इस समस्या को दूर करने के लिए विभाग ने माधव नगर की ओर नगर निगम के गारंटी पीरियड वाली सड़क को व्हाइट टॉपिंग के एस्टीमेट से अलग रखा। इस हिस्से में फिलहाल व्हाइट टॉपिंग नहीं की जाएगी। इसके चलते निर्माण मद में राशि बच गई। पीडब्ल्यूडी ने इसी बची हुई राशि से सड़क चौड़ीकरण कराने की स्वीकृति मांगी थी। अब भोपाल मुख्यालय से मंजूरी मिलने के बाद इसी सप्ताह काम शुरू करने की तैयारी है। एजी ऑफिस पुल से नाका चंद्रवदनी होते हुए विक्की फैक्ट्री तक सड़क निर्माण के बीच झांसी रोड थाने के सामने करीब 350 मीटर का हिस्सा अभी भी अधूरा है। यहां सीवर लाइन डालने के बाद सड़क निर्माण का काम रोक दिया गया है। इस हिस्से में आगे निर्माण शुरू करने से पहले कॉम्पैक्शन रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए यह जांच की जानी है कि सीवर लाइन डालने के बाद सड़क के नीचे की मिट्टी और बेस निर्धारित मानकों के अनुसार मजबूत हैं या नहीं।
नगर निगम ने अपनी ओर से कॉम्पैक्शन की ओके रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी को सौंप दी थी। इसके बावजूद ठेकेदार ने विभाग से अपनी ओर से रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग की है। अधिकारियों को उम्मीद है कि यह रिपोर्ट मिल जाएगी। पीडब्ल्यूडी के अनुसार, रिपोर्ट सकारात्मक आने के बाद ही झांसी रोड थाने के सामने वाले हिस्से में निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।

संक्षिप्त समाचार

अमेरिका-चीन के बीच बादशाहत की जंग तेज, बीजिंग ने बदले लिस्टिंग के नियम तो ट्रंप ने दी चेतावनी

नई दिल्ली, एजेंसी। ग्लोबल टेक इंडस्ट्री और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जे को लेकर अमेरिका-चीन के बीच टकराव तेज हो गया है। एक ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहां देश से बाहर डेटा सेंटर लगाने वाली अमेरिकी कंपनियों पर भारी टैक्स थोपने और 5 देशों को होने वाले एआई चिप एक्सपोर्ट पर सख्ती का ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ चीन ने भी पूंजी और डेटा के बाहरी फ्लो को रोकने



के लिए अपनी कंपनियों की विदेशी शेयर बाजारों में लिस्टिंग के नियम बेहद सख्त कर दिए हैं। इन फैसलों से अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया जैसी दिग्गज कंपनियों के सामने संकट खड़ा हो गया है।

ट्रंप ने दे दी कड़ी चेतावनी

ट्रंप ने व्हाइट हाउस में घोषणा की है कि जो अमेरिकी टेक कंपनियां देश से बाहर एआइ और कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बनाएंगी, उन पर प्रशासन भारी टैक्स लगाएगा। ट्रंप का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। मकसद यह है कि चीन ग्लोबल कंप्यूटिंग क्षमता पर कब्जा न कर सके। वैसे ट्रंप ने अभी टैक्स की दरों या नियमों का खुलासा नहीं किया है। लेकिन, स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद अमेरिकी राज्यों से अपील की है कि वे अपने यहां डेटा सेंटर लगाने की अनुमति दें। ट्रंप के इस ऐलान से अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी दिग्गज क्लाउड कंपनियों की ग्लोबल योजनाओं को बड़ा झटका लग सकता है।

भैंस का दूध 6 और गाय का दूध 4 प्रति लीटर हुआ महंगा

नईदिल्ली, एजेंसी। दूध की आवश्यकता हर एक घर में है। ऐसे में दूध का रेट बढ़ने का सीधा असर आम-आदमी की जेब पर पड़ता है। कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटिव मिल्क प्रोडक्यूसर्स यूनियन (प्रचलित नाम गोकुल मिल्क यूनियन) ने दूध के रेट में इजाफा किया है। भैंस के दूध का रेट इस यूनियन ने 6 रुपये प्रति लीटर और गाय के दूध में 4 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया है। इसकी जानकारी संगठन के चेयरमैन राजेश पाटिल ने दी है। बता दें, बढ़े हुए रेट शनिवार से ही लागू कर दिए गए हैं।



राजेश पाटिल ने बताया कि यह फैसला सभी 25 डायरेक्टर्स ने सूखे के हालात को देखते हुए लिया है। बता दें, इसके अलावा संगठन ने किसानों से दूध खरीदने के रेट में भी इजाफा किया है। 3 रुपये प्रति लीटर भैंस के दूध में और 2 रुपये प्रति लीटर गाय के दूध में इजाफा किया गया है। यह नया रेट मार्च यानी 131 दिनों तक लागू रहेगा।

मदर डेयरी और अमूल ने भी बढ़ाया है रेट

इस साल अमूल और मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में दो बार इजाफा किया है। 12 नवंबर को गुजरात कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने फ्रेश मिल्क के पैक की कीमतों में 2 से 4 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया है। अमूल ताजा का रेट 2 रुपये प्रति लीटर मंहगा हो गया है। वहीं, अमूल गोल्ड फुल क्रीम का रेट 4 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ गया है।

अडानी की कंपनी को मिला 25 साल का बड़ा ऑर्डर, पश्चिम बंगाल को 1750 एमडब्ल्यू बिजली की करेगी सप्लाई

नई दिल्ली, एजेंसी। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस को पश्चिम बंगाल में बिजली सप्लाई का बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी पावरपल्स ट्रेडिंग सॉल्यूशंस को पश्चिम बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से 1750 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की सप्लाई के लिए लेटर ऑफ अवॉर्ड मिला है। यह सप्लाई 25 साल तक की जाएगी। इस समझौते में 750 मेगावाट अतिरिक्त बिजली सप्लाई का विकल्प भी शामिल है। अगर पश्चिम बंगाल की कंपनी इस विकल्प का इस्तेमाल करती है, तो कुल बिजली सप्लाई की क्षमता बढ़कर 2,500 मेगावाट हो जाएगी।

जुलाई 2028 से शुरू होगी सप्लाई- अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के मुताबिक, शुरुआती 1750 मेगावाट बिजली की सप्लाई 1 जुलाई 2028 से शुरू होगी। वहीं अतिरिक्त 750 मेगावाट का विकल्प इस्तेमाल किए जाने पर इसकी सप्लाई 1 अप्रैल 2029 से शुरू होगी। कंपनी की सब्सिडियरी को प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया और ई-रिवर्स ऑक्शन के बाद यह ऑर्डर मिला है।



दिन-रात मिलेगी बिजली

इस समझौते की खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल को चौबीसों घंटे रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा मिलेगी। आमतौर पर सोलर पावर का उत्पादन दिन में और विंड पावर का उत्पादन हवा की उपलब्धता पर निर्भर करता है। ऐसे में बैटरी स्टोरेज और दूसरे इंतजामों की मदद से बिजली की सप्लाई लगातार बनाए रखी जाती है।

कंपनी के मुताबिक इस तरह की बिजली सप्लाई से रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही बिजली ट्रांसमिशन सिस्टम का बेहतर इस्तेमाल भी हो सकेगा।

चौबीसों घंटे रिन्यूएबल एनर्जी की सप्लाई भारत के ऊर्जा बदलाव के लिए अहम होगी। इससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ ट्रांसमिशन सिस्टम का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी।

4.6 जीडब्ल्यू सोलर-विंड क्षमता से जुड़ी कंपनी - अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने बताया कि उसकी सब्सिडियरी ने बिजली की सप्लाई के लिए करीब 4.6 गीगावाट सोलर और विंड पावर क्षमता का इंतजाम किया है। इसके अलावा, कंपनी ने 3.5 गीगावाट-घंटे की बैटरी एनर्जी स्टोरेज क्षमता भी जोड़ी है।

कंपनी को मिलेगा फायदा

यह 25 साल का समझौता अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस को बिजली सप्लाई के कारोबार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने का मौका देगा। वहीं, पश्चिम बंगाल को लंबे समय तक रिन्यूएबल एनर्जी की सप्लाई का इंतजाम मिलेगा। बिजली की सप्लाई जुलाई 2028 से चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी।

कितने घर होंगे रोशन

औसतन 1 मेगावाट बिजली से लगभग 750 से 1000 घरों की जरूरत पूरी होती है। यानी कुल 2500 मेगावाट बिजली से पश्चिम बंगाल के करीब 18 से 22 लाख घरों को 24 घंटे स्वच्छ बिजली मिल सकेगी। वहीं कोयले से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होने से न केवल कार्बन उत्सर्जन घटेगा, बल्कि पीक डिमांड में होने वाली बिजली कटौती से भी बड़ी राहत मिलेगी।

क्या है शेयर की स्थिति

अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर ने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। बीएसई पर कंपनी के शेयर शुक्रवार को करीब 1 फीसदी की तेजी के साथ 1486.20 रुपये पर बंद हुए थे। पिछले एक महीने में इसमें 12 फीसदी की तेजी आई है। वहीं इस साल इस कंपनी के शेयर ने 42 फीसदी और पिछले एक साल में 52 फीसदी का रिटर्न दिया है।

ऐमजॉन, बिगबास्केट, स्विगी इंस्टामार्टः डार्क स्टोर में सरकार कर रही है कार्रवाई



नई दिल्ली, एजेंसी। महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने पुणे स्थित ऐमजॉन और बिगबास्केट के दो डार्क स्टोर का फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। फूड सिक्योरिटी और साफ-सफाई के नियमों का गंभीर उल्लघंन पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। यह पहला मौका नहीं है जब अथॉरिटीज में क्विक कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की है। इससे पहले दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद समेत कई शहरों में क्विक कॉमर्स कंपनियों के डार्क स्टोर्स के खिलाफ एक्शन लिया गया है। लेकिन इसके बावजूद ये कंपनियां सुधर नहीं रही हैं।

एफडीए ने शनिवार को पुणे के सिंहगढ़ रोड पर स्थित ऐमजॉन और बिगबास्केट के डार्क स्टोर्स के फूड लाइसेंस सस्पेंड किए। अधिकारियों का दावा है कि जांच के दौरान वहां एक्सपायर हो चुकी मिठाइयां और फंगस लगे फूड आइटम्स मिले। साथ ही खाने-पीने की चीजों को साबुन के साथ स्टोर किया गया था। इसके बाद खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की गई।

क्या होते हैं डार्क स्टोर- डार्क स्टोर रिटेल स्टाइल की फैसिलिटी या वेयरहाउस होते हैं। इन्हें खास तौर पर ऑनलाइन ऑर्डर पूरे करने के लिए बनाया जाता है। ये एक तरह के छोटे सप्लाई सेंटर होते हैं। इनमें आम ग्राहकों का आना-जाना नहीं होता, इसलिए इन्हें डार्क कहा जाता है।

पीएम मोदी और रघुराम राजन के सवालों के घेरे में भारतीय उद्योगपति, छूट से पहले देना होगा जवाब

नई दिल्ली, एजेंसी। आम बजट 2027-28 से ठीक पहले केंद्र सरकार और भारतीय कॉर्पोरेट जगत के बीच रिश्ते में नया मोड़ आ गया है। बीते गुरुवार को फिक्की की सालाना आम बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्योगपतियों की रियायतों की असीम भूख पर तंज कसते हुए सीधा सवाल पूछा था। यह कि कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स में भारी राहत दिए जाने के बावजूद कंपनियों ने कर्मचारियों का वेतन और रोजगार क्यों नहीं बढ़ाया। पीएम के इस सख्त मैसेज को बजट में नई टैक्स छूट की मांग कर रहे इंडिया इंक के लिए बड़ी चेतावनी माना जा रहा है। पीएम से पहले



आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी भारतीय निजी क्षेत्र को आईना दिखाकर सवाल कर चुके हैं कि आखिर हमारी कंपनियां सिर्फ घरेलू बाजार के मुनाफे से संतुष्ट क्यों हैं। वे इंवेस्टमेंट और इनोवेशन में पीछे क्यों रह गई हैं।

पीएम के सवालों से उद्योगपतियों में हड़कंप

आम बजट 2027-28 की चर्चाओं के बीच पीएम की फिक्की के मंच से कॉर्पोरेट जगत पर की गई तीखी प्रतिक्रियाओं ने उद्योगपतियों को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। पीएम मोदी के अनुसार, सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी किया। जीएसटी दरें कम कीं। 12 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स राहत दी। लेकिन, उद्योगों की रियायतों की भूख कभी शांत नहीं होती। पीएम ने सीधे सवाल किया कि क्या कंपनियों ने इसके बदले कर्मचारियों की सैलरी या नौकरियों की संख्या बढ़ाई इस बयान को बजट से पहले नई टैक्स छूट और लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स में राहत की मांग कर रहे कॉर्पोरेट जगत के लिए साफ चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।

आंकड़े लगा रहे हैं मुहर

सरकारी आंकड़े और सर्वे भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि कंपनियों के मुनाफे और कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के बीच बड़ा फर्क है। 2025 के आर्थिक सर्वे में बताया गया था कि 2024 में कॉर्पोरेट मुनाफा 15 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। इसके उलट कर्मचारियों पर होने वाले खर्च की ग्रोथ धीमी रही। वैसे उद्योगों के वार्षिक सर्वे के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 2024-25 में औद्योगिक रोजगार 7.2 फीसदी बढ़ा। यह बढ़कर 2.1 करोड़ हो गया। इमॉल्यूमेंट्स यानी पारिश्रमिक 12.1 फीसदी बढ़कर 8 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। वहीं, मुनाफा 7.7 फीसदी बढ़कर 11.6 लाख करोड़ रुपये रहा।

अब पीएम मोदी की नाराजगी के बाद कंपनियां आने वाले हफ्तों में रोजगार और वेतन वृद्धि से जुड़े अपने आंकड़े सरकार के सामने पेश करने की तैयारी में हैं। दूसरी ओर उद्योग जगत के अधिकारियों का कहना है कि हाल के महीनों में ईंधन और कच्चे माल की ऊंची लागत, कमजोर रुपये और ग्लोबल अनिश्चितताओं से कंपनियों पर दबाव रहा है। वैसे जीएसटी कटौती के बाद खपत बढ़ने से निजी निवेश में कुछ तेजी आई है। वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ प्री-बजट बैठक में फिक्की ने लिस्टेड शेयरों पर एलटीसीजी टैक्स छूट बहाल करने की मांग की है।

कंपनियों का मुनाफा तीन गुना, कर्मचारियों की सैलरी महंगाई से पीछे

टैक्स में 7 लाख करोड़ की बचत, लेकिन रोजगार और वेतन वृद्धि सुस्त

नईदिल्ली, एजेंसी। पीएम नरेंद्र मोदी ने फिक्की के कार्यक्रम में कंपनियों से पूछा था कि सरकार ने तो 12 लाख रुपये तक की कमाई पर इनकम टैक्स माफ कर दिया। क्या आपने अपने यहां एम्प्लॉई की तनख्वाह बढ़ाई क्या आपने अपने एम्प्लॉई की संख्या बढ़ाई देखिए क्या है हकीकत।

सरकार ने 2019 में कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की थी। सीएमआइइ के नॉन-फाइनेंशियल निफ्टी 500 कंपनियों के आंकड़ों के मुताबिक इन कंपनियों का प्रॉफिट तिगुना से ज्यादा बढ़ गया है, वेज बिल करीब दोगुना हुआ है, हायरिंग ग्रोथ 11 साल के लो पर चली गई है और एवरेज पे महंगाई के मुकाबले कम रही है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2019 में प्रॉफिट, वेज बिल और कर्मचारियों की संख्या 100 थी तो वित्त वर्ष 2026 में कंपनियों का प्रॉफिट 323, वेज बिल 195



और कर्मचारियों की संख्या 155 पहुंच गई। इस दौरान मुनाफा सालाना 18 फीसदी, वेज 10 फीसदी और कर्मचारियों की संख्या 6.5 फीसदी बढ़ी। सरकार ने सितंबर 2019 में कॉरपोरेट टैक्स 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी किया था।

पिछले दो साल का हाल

फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2024 के बीच कोरोना के बाद रिकवरी के दौर में वेज बिल में सालाना 13.7 से 14.5 फीसदी बढ़ोतरी हुई जबकि कर्मचारियों की संख्या 7 से 13 फीसदी बढ़ी। फाइनेंशियल ईयर 2023 में हायरिंग और पे की ग्रोथ प्रॉफिट से ज्यादा रही। इसमें गिरावट 2025 और 2026 में रही। इस दौरान वेज बिल की ग्रोथ आधी होकर 5.1 फीसदी और 6.1 फीसदी रही। यह एक दशक में सबसे कम है। 2026 में स्टाफ ग्रोथ 2.8 फीसदी रही जो सीएमआइइ के 11 साल के आंकड़ों में सबसे कम है। 2025 में प्रॉफि 11 फीसदी और 2026 में 22 फीसदी बढ़ा।

टॉप पर बैठा है चीन, भारत की हिस्सेदारी 0.075 प्रतिशत, साउथ कोरिया की मदद से होगा बेड़ा पार



नई दिल्ली, एजेंसी। जहाज बनाने यानी शिपबिल्डिंग के मामले में भारत अभी काफी पीछे है। सरकार ने साल 2030 तक दुनिया के टॉप 10 और 2047 तक टॉप 5 में आने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। दुनिया की बड़ी कंपनियां भी अब भारत में दिलचस्पी दिखाने लगी हैं। हाल में संपन्न इंडिया शिपबिल्डिंग कॉन्क्लेव में 30 से ज्यादा इंटरनेशनल शिपयार्ड और मेरिटाइम कंपनियों ने हिस्सा लिया। ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पोर्ट्स, शिपिंग और वॉटरवेज मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि हुंडई और सैमसंग जैसी दिग्गज कंपनियों ने स्थानीय कंपनियों के मिलकर बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने में दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने कहा, हुंडई ग्रुप की कंपनी एचडी कोरिया शिपबिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग थुथूकुड़ी में प्रस्तावित मेगा शिपयार्ड में एंकर पार्टनर बनकर उभरी है। इसमें करीब 38,000 करोड़ रुपये का निवेश आने की संभावना है। सोनोवाल ने दावा किया कि भारत का शिपबिल्डिंग आउटपुट मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में 80 फीसदी से ज्यादा बढ़ा है और इसके 100000 ग्रॉस टन के पार जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि देश में शिपबिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार 69,725 करोड़ रुपये का शिपबिल्डिंग इंसेंटिव पैकेज लाई है। साथ ही 25,000 करोड़ रुपये का एक मेरिटाइम डेवलपमेंट फंड भी बनाया गया है। हुंडई और सैमसंग जैसी दिग्गज कंपनियों ने स्थानीय कंपनियों के मिलकर बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने में दिलचस्पी दिखाई है।

क्या कर रहा भारत

उन्होंने कहा कि सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज गुजरात के पीपावाव में स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज को टेक्निकल सपोर्ट दे रही है। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स ने आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड शिपबिल्डिंग क्लस्टर्स में एंकर शिपयार्ड डेवलपर के रूप में हिस्सा लेने के लिए एग्रीमेंट किए हैं। इनमें से प्रत्येक में करीब 15,000 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है।

पाकिस्तानी नाम पर दीवाना हिंदुस्तान, किचन के प्रयोग से शुरू हुई लाहौरी जीरा यूं बनी 2,800 करोड़ की कंपनी

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के नॉन-अल्कोहलिक बेवरेज मार्केट में इन दिनों एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। विदेशी कोला ब्रांड्स के मुकाबले देसी स्वाद वाले जीरा सोडा की डिमांड तेजी से बढ़ी है। इस क्रांति का सबसे बड़ा चेहरा है लाहौरी जीरा। इसका नाम पाकिस्तान के शहर लाहौर से इंस्पायर्ड है। पंजाब के तीन कजिन्स ने 2017 में इस ब्रांड की नींव रखी थी। अमृतसर की वाघा-अटारी सीमा से सिर्फ 50-55 किमी दूर बसे लाहौर की साझा सांस्कृतिक विरासत और बचपन की यादों को भुनाने के मकसद से ऐसा किया गया था। सिर्फ 10 रुपये की कीमत और अपना देसी ठंडा की टैगलाइन के साथ इस ब्रांड ने आम भारतीयों का दिल जीता है। इतना ही नहीं, विदेशी कोला कंपनियों के एकाधिकार को तोड़कर करोड़ों रुपये का कारोबार खड़ा कर लिया है।

घर के किचन का प्रयोग हुआ हिट- पंजाब के तीन चचेरे भाइयों सौरभ मुंजाल, निखिल डोडा और सौरभ भुटना ने 2016 में घर के किचन में काला नमक, जीरा पाउडर और नींबू के रस से एक देसी ड्रिंक तैयार किया। इसे 2017 में उन्होंने लाहौरी जीरा के रूप में बाजार में उतारा। ब्रांड का नाम पाकिस्तान के लाहौर पर रखने के पीछे एक खास वजह थी। विभाजन से पहले की साझा पंजाबी संस्कृति और वाघा-अटारी सीमा से सिर्फ 50-55 किमी दूर बसे लाहौर से जुड़ी पुरानी यादों को जिंदा करने के लिए उन्होंने यह नाम चुना।



2,800 करोड़ की वैल्यूएशन

बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए लाहौरी जीरा की मूल कंपनी आर्कियन फूड्स ने पिछले साल अपनी प्रोडक्शन कैपिसिटी दोगुनी बढ़ाकर 12 लाख बोतल रोजाना कर दी है। फिर भी कंपनी के सीईओ सौरभ मुंजाल के मुताबिक मांग के मुकाबले सप्लाई कम पड़ रही है। मई 2025 में मोतीलाल ओसवाल वेल्थ से 200 करोड़ रुपये का निवेश जुटाने के बाद कंपनी की वैल्यूएशन 2,800 करोड़ रुपये हो गई है। आज इसमें 1,800 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं।

160 एमएल की बोतल को सिर्फ 10 रुपये की किफायती कीमत पर बेचकर इस ब्रांड ने टीयर-2, टीयर-3 शहरों और ग्रामीण बाजारों में तेजी से पैठ बनाई।

कंपनी का रेवेन्यू वित्त वर्ष 2023-24 के 312 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में करीब 775 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। अब यह इस साल करीब 1,112 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने की तैयारी में है।

मार्केट में पैदा कर दी है हलचल

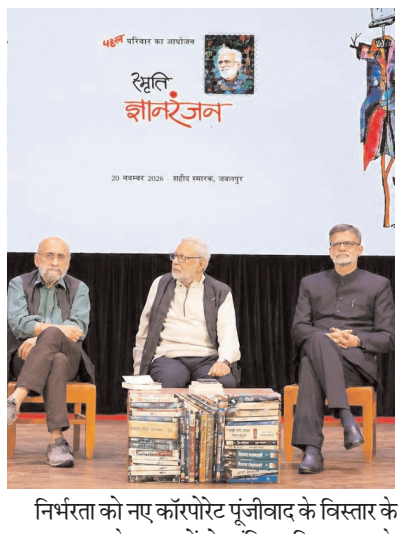
लाहौरी जीरा की इस कामयाबी ने भारत के 32 अरब डॉलर के बेवरेज मार्केट में हलचल पैदा कर दी है। कोटक म्यूचुअल फंड की एक रिपोर्ट के अनुसार, लाहौरी जीरा, रिलायंस के कैंपा जीरा, पार्ले एग्रो के ढिशूम और बिंदू के फिज जीरा जैसे देसी ब्रांड्स ने मिलकर भारत के कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में अपनी हिस्सेदारी दोगुनी कर करीब 15 फीसदी तक पहुंचा ली है। इसके चलते कोका-कोला और पेप्सीको की ज्वाइंट मार्केट हिस्सेदारी 93 फीसदी से घटकर 85 फीसदी रह गई है। ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर भी इन गर्मियों में जीरा सोडा के ऑर्डर में 900 फीसदी तक का उछाल देखा गया है। इसके दबाव में अब कोका-कोला को भी अपने पुराने जीरा ब्रांड रिमझिम का प्रोडक्शन दोगुना करना पड़ा है।

स्मृति ज्ञानरंजन' में लोकतंत्र, कॉरपोरेट वर्चस्व और वैश्विक राजनीति पर विमर्श

कॉरपोरेट पूंजीवाद का बदल रहा चेहरा, देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात: परंजय गुहा

एक सत बुलेटिन, जबलपुर

साहित्यिक पत्रिका 'पहल' के संपादक और प्रतिष्ठित कथाकार ज्ञानरंजन की जन्मतिथि की पूर्व संध्या पर शहीद स्मारक में आयोजित 'स्मृति ज्ञानरंजन' कार्यक्रम में कॉरपोरेट पूंजीवाद, लोकतंत्र और समकालीन वैश्विक राजनीति के अंतर्संबंधों पर गंभीर विमर्श हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, वरिष्ठ पत्रकार एवं आर्थिक-राजनीतिक विश्लेषक परंजय गुहा ठाकुरता ने कहा कि पूरी दुनिया में पूंजीवाद का चेहरा और स्वरूप तेजी से बदल रहा है। भारत की मौजूदा परिस्थितियों पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात बन रहे हैं। 'कॉरपोरेट पूंजीवाद और लोकतंत्र' विषय पर केंद्रित इस आयोजन में वक्ताओं ने ज्ञानरंजन के साहित्यिक अवदान के साथ उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता और लोकतांत्रिक चेतना को भी याद किया। परंजय गुहा ठाकुरता ने कहा कि भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी का व्यापक विस्तार केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था और समाज की संरचना में आ रहे बड़े परिवर्तनों का संकेत है। उन्होंने मोबाइल और डिजिटल माध्यमों पर बढ़ती



निर्भरता को नए कॉरपोरेट पूंजीवाद के विस्तार के उदाहरण के रूप में रेखांकित किया। उनके अनुसार, देश की लगभग 145 करोड़ आबादी मोबाइल के शिकंजे में जकड़ गई है। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि राजनीतिक नेतृत्व और नौकरशाही के प्रभाव ने उसकी स्वायत्तता को कमजोर किया है। इसका परिणाम यह है कि आधारभूत क्षेत्रों में कुछ बड़े निजी औद्योगिक घरानों का वर्चस्व बढ़ा है। उन्होंने कॉरपोरेट हितों के बढ़ते प्रभाव को लोकतांत्रिक व्यवस्था, आर्थिक समानता और सार्वजनिक संसाधनों के इस्तेमाल से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के रूप में प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश दुबे ने ज्ञानरंजन के साहित्यिक अवदान और 'पहल' की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि अक्षर से शब्द तक पहुंचने और सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। उन्होंने ज्ञानरंजन की पुस्तकों और 'पहल' को साहित्य के क्षेत्र में एक सशक्त वैचारिक औजार बताया। समकालीन कॉरपोरेट पूंजीवाद की अराजकता पर टिप्पणी करते हुए प्रकाश दुबे ने कहा कि कुछ लोग अपने व्यावसायिक हितों के लिए सौदेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने मौजूदा व्यवस्था की विडंबना को रेखांकित करते हुए कहा कि कॉरपोरेट पूंजीवाद एक ऐसे ट्रक की तरह हो गया है, जिसमें हम सभी बैठे हैं। वैश्विक राजनीति के संदर्भ में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार्यशैली पर टिप्पणी करते हुए उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनमानी करने वाला 'ग्लोबल डिक्टेटर' बताया। विशिष्ट अतिथि कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल ने ज्ञानरंजन से जुड़े अपने संस्मरण साझा किए।

डॉक्यूमेंट्री और चित्र प्रदर्शनी

कार्यक्रम में साहित्यिक और दृश्य माध्यमों के जरिए ज्ञानरंजन की रचनात्मक यात्रा को याद किया गया। कथाकार राजेंद्र दानी ने 'पहल' के प्रथम अंक के संपादकीय का वाचन किया। यह संपादकीय चिली की घटनाओं और वहां के राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ा था। इसके माध्यम से पत्रिका की आरंभिक वैचारिक दिशा और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक सरोकारों की झलक सामने आई। संजय जोशी की डॉक्यूमेंट्री में ज्ञानरंजन के साक्षात्कार का एक अंश भी प्रदर्शित किया गया, जिसमें उन्होंने 'पहल' की शुरुआत से जुड़े अनुभव साझा किए थे। आयोजन स्थल पर चित्रकार अवधेश बाजपेयी द्वारा ज्ञानरंजन और 'पहल' पर केंद्रित चित्रों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रही। इन प्रस्तुतियों ने साहित्य, राजनीति, स्मृति और कला के बीच संवाद को साकार किया। कार्यक्रम में विवेक चतुर्वेदी, भारती वत्स और अजय यादव ने अतिथियों का स्वागत किया। संचालन राजीव कुमार शुक्ल ने किया तथा आभार हिमांशु राय ने व्यक्त किया। आयोजन को सफल बनाने में प्रगतिशील लेखक संघ, विवेचना रंगमंडल, विवेचना थिएटर ग्रुप, रंगाभरण थिएटर ग्रुप, समागम रंगमंडल, रचना समय, मध्यप्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन और अन्विति सहित विभिन्न साहित्यिक-सांस्कृतिक संस्थाओं की सक्रिय सहभागिता रही।

सम्यक दर्शन आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है : प्रबुद्ध सागर जी



एक सत बुलेटिन, जबलपुर

डी.एन. जैन हाउसिंग बोर्ड सोसायटी के तत्वावधान में आयोजित 27 मंडलीय समवशरण विधान में सोमवार को श्रद्धा और भक्ति का अनूठा वातावरण रहा। विधान के दौरान श्रद्धालुओं ने 512 अर्घ्य समर्पित कर भगवान की आराधना की। विधान की धार्मिक क्रियाएं प्रातःकाल सौधर्म इंद्र और चक्रवर्ती राजा के स्वरूप में संपन्न हुईं। सभी इंद्रों ने श्रीजी का अभिषेक कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इसके पश्चात विधानाचार्य बाल ब्रह्मचारी रविंद्र भैया ने विधि-विधान के साथ श्रद्धालुओं से अर्घ्य समर्पित कराए। धर्मसभा को संबोधित करते हुए मुनिश्री प्रबुद्धसागर महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति आगे बढ़ने और चलने का प्रयास करता है, उसके भीतर नई ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार होता है। सफलता उसी को प्राप्त होती है, जो कदम बढ़ाने का साहस करता है। केवल इच्छा करने से लक्ष्य हासिल नहीं होता, उसके लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। मुनिश्री ने कुंद-कुंद देव के प्रवचनसार का उल्लेख करते हुए कहा कि निश्चय से चारित्र ही धर्म है। चारित्र के मार्ग पर चलकर ही जीव अनंत शांति को प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक जीव का लक्ष्य ऐसा शाश्वत सुख प्राप्त करना होना चाहिए, जिसके बाद संसार की पीड़ा और दुखों से मुक्ति मिले। उन्होंने सम्यक दर्शन की महत्ता बताते हुए कहा कि यह आत्मा की अपनी परिणति है। देव, शास्त्र और गुरु इसके निमित्त बनते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन की अनुभूति स्वयं की आत्मा में होती है। आयोजन में डी.एस. जैन बोर्डिंग हाउस सोसायटी के प्रधानमंत्री संजय सिंघई इस्ती आनंद सिंघई, समीर सिंघई, पंकज सिंघई एवं प्रभात जैन सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

संत रविदास आश्रम में महिलाओं के द्वारा घरेलू कामगार महिला संगठन का गठन



एक सत बुलेटिन, जबलपुर

नागरिक अधिकार मंच के द्वारा संत रविदास आश्रम में घरेलू कामगार महिलाओं के सम्मलेन आयोजित लिया गया । इस कार्यक्रम में पोलीपथर, चंडाल भाटा, दमोह नाका, मादोताल और सुभाष नगर अधारताल से 70 घरेलू कामगार महिलाए उपस्थित रही। सर्वप्रथम साथी भावेश के द्वारा कार्यक्रम में आई महिला साथियों का स्वागत और अभिवादन किया गया, उसके उपरांत साथी पूजा भुर्रक के द्वारा कार्यक्रम का उ?द्देश्य बताते हुए कहा कि इस कार्यक्रम प्रमुख उद्देश्य समस्त घरेलू कामगार महिलाओं को संगठित करना और उनको एक संगठन का स्वरूप देना । कार्यक्रम में आये समस्त महिलाओं को संबोधित करते हुए साथी शिव कुमार ने बताया की आज के दौर में घरेलू कामगार मजदूरों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, घरेलू कामगारों में 93 प्रतिशत महिलाएं हैं, इनके कार्य न करने से माध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, और शहरों की गति भी प्रभावित होती है आज घरेलू कामगार महिलाओं के काम के घंटे, न्यूनतम मजदूरी, साप्ताहिक अवकाश, दुर्घटना बीमा जैसी कोई सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है।

रानी दुर्गावती अस्पताल में आज शुरू होगा प्रदेश का सबसे बड़ा मिल्क बैंक अमृत कलश

अब कमजोर नवजातों को नहीं होगी मां के दूध की कमी बीमार शिशुओं के लिए होगी मातृ दुग्ध की व्यवस्था

एक सत बुलेटिन, जबलपुर

नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य और जीवन रक्षा की दिशा में महाकौशल को मंगलवार को एक बड़ी स्वास्थ्य सुविधा मिलने जा रही है। रानी दुर्गावती चिकित्सालय में मध्यप्रदेश के सबसे बड़े एवं महाकौशल के पहले कॉम्प्रिहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर मिल्क बैंक 'अमृत कलश' का शुभारंभ 24 नवंबर को लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह करेंगे। करीब 70 लाख रुपये की लागत से तैयार इस सेंटर के माध्यम से जरूरतमंद नवजात शिशुओं को सुरक्षित मातृ दुग्ध उपलब्ध कराया जा सकेगा। माताओं के दान किए दूध से बचेगी नवजातों की जिंदगी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से जारी जानकारी के अनुसार, जन्म के बाद शिशु के लिए मां का दूध अमृत के समान होता है। यह नवजात की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और उसके समुचित शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई बार समय से पहले जन्म लेने, कम वजन या बीमारी के कारण नवजात शिशु मां का दूध प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों के लिए



मिल्क बैंक बड़ी मददगार सुविधा साबित होगा। स्वेच्छा से दूध दान करने वाली माताओं से होगा संग्रह इस सेंटर में ऐसी धात्री माताओं का दूध स्वेच्छा और सहमति से एकत्रित किया जाएगा, जिन्हें पर्याप्त मात्रा में दूध उपलब्ध होता है और जो जरूरतमंद बच्चों के लिए दूध दान करना चाहती हैं। अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से सुरक्षित संरक्षित किया जाएगा। इसके बाद एसएनसीयू और एनआरसी में भर्ती बीमार एवं कम वजन वाले नवजात शिशुओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इस व्यवस्था से बीमार नवजात शिशुओं को आवश्यक मातृ दुग्ध मिल सकेगा। इससे उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार और रिकवरी में मदद मिलने के साथ शिशु मृत्यु दर कम करने के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी। 'अमृत कलश' मिल्क बैंक नवजात शिशुओं की देखभाल और मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में जबलपुर के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

28 को श्री अजित वर्मा स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार समारोह



जबलपुर। प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यिक, सांस्कृतिक संस्था मित्रसंघ के संस्थापक जबलपुर पत्रकार संघ के पूर्व अध्यक्ष तथा दैनिक जयलोक के संस्थापक श्री अजित वर्मा जी की स्मृति में पत्रकारिता पुरस्कार समारोह 28 नवंबर को अपरान्ह 3.30 बजे से होटल सत्य अशोका में मित्रसंघ द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में आशीषदाता ब्रह्मचारी श्री चैतन्यानंद जी महाराज रहेंगे। मुख्य अतिथि लोकसभा सांसद आशीष दुबे, अध्यक्षता महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, विशिष्ठ अतिथि विधायक अजय विश्नोई, अशोक रोहाणी, भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री अखिलेश जैन, पूर्व विधायक विनय सक्सेना उद्योगपति संदीप विजन तथा सौरभ बड़ेरिया रहेंगे।

बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर महर्षि गौतम आश्रम से निकली आस्था और अध्यात्म की अनुपम यात्रा

एक सत बुलेटिन, जबलपुर

श्री नर्मदा संकीर्तन परिक्रमा (पंजी.) समिति, जबलपुर के तत्वावधान में बैकुंठ चतुर्दशी के पावन अवसर पर महर्षि गौतम आश्रम, गोपालपुर, भेड़ाघाट में भव्य नर्मदा परिक्रमा का आयोजन श्रद्धा एवं आध्यात्मिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ। प्रातः 5:30 बजे सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ हुआ। इसके पश्चात समिति के संरक्षक जगदुरु स्वामी राघवदेवाचार्य महाराज ने मां नर्मदा मैया एवं श्री हनुमान जी महाराज का विधिवत पूजन-अर्चन कर 108 दीपों से भव्य महाआरती की। इसी अवसर पर चातुर्मास समापन के उपलक्ष्य में मां नर्मदा का दुग्धाभिषेक भी किया गया। तत्पश्चात प्रातः 8:30 बजे शंखनाद के साथ भव्य परिक्रमा का शुभारंभ हुआ। समिति के संस्थापक पंडित मनमोहन दुबे, विकास प्राधिकरण अध्यक्ष



संदीप जैन, के नेतृत्व में श्रद्धालु पीत धर्मध्वज लेकर सीताराम संकीर्तन, मां नर्मदा के भक्तिमय भजनों एवं 'नर्मदे हर' के जयघोष के साथ परिक्रमा के लिए रवाना हुए। समिति के सचिव देवेंद्र नेमा ने बताया कि परिक्रमा पूर्ण कर लौटे श्रद्धालुओं ने सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ एवं जयघोष के साथ कार्यक्रम का समापन किया। इसके उपरांत आश्रम परिसर में आयोजित भंडारे में सभी उपस्थित भक्तजनों ने प्रसादी ग्रहण की।

अध्यक्ष के आगमन पर जिला कोर्ट में दिखा उत्साह, बार पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने की अगवानी

स्टेट बार अध्यक्ष का जिला कोर्ट में स्वागत एवं अभिनंदन

एक सत बुलेटिन, जबलपुर

जिला न्यायालय परिसर में सोमवार को जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर की ओर से मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष शैलेन्द्र वर्मा एवं परिषद के अन्य पदाधिकारियों का स्वागत एवं अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मनीष मिश्रा एवं सचिव शैलेन्द्र सिंह ठाकुर ने बताया कि समारोह में राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष शैलेन्द्र वर्मा, चेयरमैन मनीष तिवारी, चेयरमैन सुनील मिश्रा,



चेयरमैन राशिद सुहेल सिद्दीकी, आर.के. सिंह सैनी, नवीन शुक्ला तथा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शशांक शेखर का स्वागत किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष शैलेन्द्र वर्मा ने कहा कि अधिवक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही बीमा योजना, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन जिला अधिवक्ता संघ के सचिव शैलेन्द्र सिंह ठाकुर ने किया, जबकि उपाध्यक्ष सुनीता गुप्ता ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ की महिला उपाध्यक्ष सुनीता सूद , सहसचिव शैलेन्द्र यादव, कोषाध्यक्ष नेहा मिश्रा, पुस्तकालय सचिव रविंद्र दत्त, सांस्कृतिक समन्वयक शारदा जायसवाल सहित कार्यकारिणी सदस्य एवं बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।

सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने सुबह 7 बजे वार्डों में पहुंचे निगमायुक्त अग्रिम कुमार

सफाई व्यवस्था में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, फील्ड में रहकर कार्य करें अधिकारी: निगमायुक्त

एक सत बुलेटिन, जबलपुर

सफाई व्यवस्था को शत-प्रतिशत जमीनी धरातल पर उतारने और स्वच्छता कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निगमायुक्त अग्रिम कुमार सोमवार सुबह 7 बजे ही स्वच्छता टीम के साथ वार्डों के निरीक्षण पर पहुंचे। निगमायुक्त ने संभाग क्रमांक 3 रामपुर एवं संभाग क्रमांक 4 छेटी लाइन फाटक के अंतर्गत आने वाले वार्डों में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और सफाई मित्रों की उपस्थिति का मौके पर सत्यापन किया। निगमायुक्त ने केवल उपस्थिति रजिस्टर तक सीमित न रहते हुए स्वयं कार्यस्थलों पर पहुंचकर सफाई मित्रों की मौजूदगी एवं उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक वार्ड में सभी 29 सफाई मित्र उपस्थित होकर अपने निर्धारित कार्यों में संलग्न मिले, जिस पर उन्होंने व्यवस्था को इसी तरह नियमित और प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान निगमायुक्त अग्रिम कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, मुख्य स्वच्छता निरीक्षकों, स्वच्छता निरीक्षकों एवं वार्ड सुपरवाइजरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे सुबह से ही फील्ड में उपस्थित रहकर सफाई मित्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करें।



सबसे पहले मुख्य मार्गों की सफाई कराई जाए, इसके बाद निर्धारित बीट चार्ट के अनुसार कॉलोनियों, बस्तियों एवं अंदरूनी मार्गों में भी व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण सफाई कार्य कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वार्ड में इसका प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देना चाहिए। अधिकारी और सुपरवाइजर नियमित रूप से कार्यस्थलों पर पहुंचकर सफाई कार्यों की निगरानी करें और जहां भी कमी दिखाई दे, तत्काल सुधार कराएं। निगमायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सुबह की सफाई व्यवस्था के बाद भी दिन में दोपहर 2 बजे तक किसी भी वार्ड में औचक निरीक्षण किया जा सकता है। इसलिए सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने निर्धारित दायित्वों के प्रति सतर्क और जवाबदेह रहें तथा सफाई व्यवस्था में निरंतरता बनाए रखें। उन्होंने स्पष्ट किया कि नई सफाई व्यवस्था लागू होने के साथ ही उसकी प्रभावी मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि नागरिकों को स्वच्छ वातावरण और बेहतर सफाई सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। निगमायुक्त अग्रिम कुमार ने स्वास्थ्य अमले एवं डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण कार्य में लगे सुपरवाइजरों की जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण बताते हुए निर्देश दिए कि वे प्रतिदिन वार्डों में जाकर कम से कम 10 नागरिकों से संवाद करें और सफाई व्यवस्था के संबंध में फीडबैक प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि नागरिकों से सीधे संवाद करने से सफाई व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा तथा यदि कहीं कोई शिकायत या कमी है तो उसे तत्काल दूर किया जा सकेगा।

एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की रोकथाम के लिए दवाओं के विवेकपूर्ण उपयोग और जनजागरूकता पर दिया जोर

स्वस्थ भारत के निर्माण में फार्मासिस्टों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण : उप मुख्यमंत्री राजेन्द शुक्ल

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**





उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि फार्मेसी केवल मुनाफे का व्यवसाय नहीं, बल्कि पीड़ित मानवता की सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है। फार्मासिस्ट स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। मरीजों तक सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही दवाओं के उचित उपयोग के प्रति समाज को जागरूक करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए चिकित्सकों, फार्मासिस्टों एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी व्यक्तियों को सामूहिक उत्तरदायित्व के भाव से कार्य करना होगा। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल भोपाल के रवीन्द्र भवन स्थित हंसध्वनि सभागार में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य फार्मेसी काउंसिल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित विश्व फार्मासिस्ट दिवस एवं राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह-2026 के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन 'स्वस्थ भारत : एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से मुकाबला' विषय पर किया गया। आयुष्मान भारत योजना ने गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग के लिए गुणवत्तापूर्ण उपचार की राह आसान की उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आयुष्मान भारत योजना ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं में ऐतिहासिक परिवर्तन किया है। इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच सुगम हुई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार केवल महानगरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। टियर-2 एवं टियर-3 शहरों में भी आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं तथा सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के नागरिकों को अपने निकटतम स्वास्थ्य संस्थान में ही बेहतर जांच, आवश्यक दवाइयां और गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध हो। स्वास्थ्य अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण, विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता तथा आधुनिक चिकित्सा तकनीकों के विस्तार की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। एंटीबायोटिक दवाओं का अनावश्यक उपयोग गंभीर चुनौती, जनजागरूकता आवश्यक उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बढ़ती चुनौती पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि एंटीबायोटिक दवाओं का अनावश्यक एवं अनुचित उपयोग जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। बिना चिकित्सकीय परामर्श के एंटीबायोटिक का सेवन तथा आवश्यकता से अधिक या गलत तरीके से इनका उपयोग रोगाणुओं में दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने का कारण बनता है।

कलेक्टर के निर्देशन में जिला पंचायत सीईओ इला तिवारी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**



कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती इला तिवारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में डीएलसीसी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित बैंको के प्रतिनिधियों से बैंकवार प्राप्त प्रकरणों के निराकरण एवं निर्धारित किए गए लक्ष्य के संबंध में जानकारी लेने के पश्चात सीईओ श्रीमती तिवारी ने कहा कि केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के प्रकरण कई बैको में लक्ष्य के अनुरूप निराकरण नही किए गए है। जो अत्यन्त ही खेदजनक है। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुयें निर्देश दिए कि सभी बैंकर्स जो प्रकरण स्वीकृत हो गये उनका वितरण एक सप्ताह के अंदर किया जाना सुनिश्चित कर तथा ऐसे प्रकरण जो अभी तक लंबित है उनका निराकरण 15 दिवस के अंदर किया जाकर हितग्राही को लाभ वितरित कर अवगत करायें ताकि निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति की जा सके। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष के लक्ष्य के अनुरूप प्रकरणों का निराकरण भी सुनिश्चित किया जाए।बैठक के दौरान सीईओ श्रीमती तिवारी ने विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि बैंको में भेजे गये प्रकरणों की लगातार मॉनीटरिंग करे ताकि निर्धारित समय पर लंबित प्रकरणों का निराकरण कर लाभ सुनिश्चित हो। बैंकर्स के साथ विभागीय अधिकारी संयुक्त रूप से प्रकरणों की जॉच करें। यदि लाभार्थी के आवेदन के संबंध में किसी भी दस्तावेज की कमी हो उसे विभागीय अधिकारी पूर्ण करवाएं। वही बैंकर्स को निर्देश दिए कि किसी प्रकरण के निराकरण करने में यदि कोई कठिनाई आ रही है तो संबंधित विभाग के साथ-साथ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय को भी अवगत करायें। समीक्षा के दौरान पशुपालन, मत्स्य, स्व-सहायता समूह, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओ के प्रकरण जो बैको में भेजे गये है।

लकड़ी पर उकेरे सपने, हुनर से लिख रहीं दुर्गा आत्मनिर्भरता की नई इबारत, अब हर महीने 6 से 8 हजार रुपये की कमाई

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**



लकड़ी के बेजान टुकड़ों में खूबसूरत आकृतियां उकेरते दुर्गा सिंह के हाथ केवल कलाकृतियां ही नहीं गढ़ रहे, बल्कि आत्मनिर्भर भविष्य के सपनों को भी आकार दे रहे हैं। उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद भी जब आर्थिक परिस्थितियों ने आगे बढ़ने की राह कठिन बनाई, तो दुर्गा ने निराश होने के बजाय अपने हुनर को अपनी ताकत बना लिया। शहडोल जिले के छोटे से गांव छतवई की दुर्गा अपनी मेहनत, लगन और कलात्मक प्रतिभा से महिला सशक्तिकरण की एक प्रेरक कहानी लिख रही है। वर्ष 2019 में मनोविज्ञान विषय से एमए करने के बाद दुर्गा ने सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की। पिता की मजदूरी से चलने वाले परिवार की आर्थिक परिस्थितियां उनके सामने बड़ी चुनौती थीं। मां गृहिणी हैं और परिवार में तीन बहनें तथा एक भाई हैं। सीमित आय के बीच अपने सपनों को पूरा करना आसान नहीं था, लेकिन दुर्गा ने परिस्थितियों के सामने हार मानने के बजाय कुछ नया सीखकर अपने पैरों पर खड़े होने का संकल्प लिया। उन्होंने सबसे पहले सिलाई-बुनाई सीखी। इसके बाद ब्यूटी पार्लर का काम भी सीखने का प्रयास किया। इन कार्यों से अपेक्षित आमदनी नहीं हुई, लेकिन हर अनुभव ने उन्हें कुछ नया करने की प्रेरणा दी। इसी तलाश ने उन्हें छतवई के हथकरघा एवं हस्तशिल्प केंद्र तक पहुंचाया, जहां उनके जीवन को एक नई दिशा मिली। हस्तशिल्प केंद्र में दुर्गा ने सबसे पहले जनजातीय गोंडी चित्रकला का प्रशिक्षण लिया। रंगों, रेखाओं और पारंपरिक आकृतियों की दुनिया से जुड़ते ही उनकी कलात्मक प्रतिभा निखरने लगी। इसी दौरान उनकी रुचि काष्ठ शिल्प की ओर बढ़ी। उन्होंने लकड़ी पर चित्रांकन और आकर्षक कलाकृतियां बनाने की बारीकियां सीखना शुरू किया। महज एक महीने के अभ्यास में दुर्गा ने अपनी लगन और कलात्मक समझ से प्रशिक्षकों को प्रभावित किया है। आज वह लकड़ी पर सुंदर आकृतियां उकेरने के साथ अपनी कल्पनाशीलता को कलाकृतियों में ढाल रही हैं। गोंडी चित्रकला का ज्ञान उनके काष्ठ शिल्प को और अधिक आकर्षक बनाने में मदद कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस हुनर को दुर्गा ने सीखने की शुरुआत की थी, वही अब उनकी कमाई का जरिया भी बन रहा है। वर्तमान में वह काष्ठ शिल्प से प्रतिमाह लगभग 6 से 8 हजार रुपये अर्जित कर रही हैं। यह आमदनी भले ही अभी सीमित हो, लेकिन दुर्गा के लिए इसका महत्व कहीं अधिक है।

खेलते-खेलते घर की राह भटका 05 वर्षीय बालक

भोपाल। थाना ऐशबाग क्षेत्र में पुष्पा नगर भारत पेट्रोल पंप पास एक 05 वर्षीय बालक मिला है, जो घर का रास्ता भटक गया है, पुलिस सहायता की आवश्यकता है। सूचना राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल-112 भोपाल में दिनाँक 23/11/2026 को सुबह 09:11 बजे प्राप्त हुई। सूचना प्राप्ति पर तत्काल ऐशबाग थाना क्षेत्र में तैनात डायल-112 वाहन को मदद के लिए रवाना किया गया। डायल-112 स्टाफ प्रधान आरक्षक गौरव प्रताप सिंह एवं पायलेट हेमंत दुबे ने मौके पर पहुँचकर बालक को अपने संरक्षण में लिया। बालक अपने बारे में कोई जानकारी नहीं दे पा रहा था। डायल-112 जवानों द्वारा आसपास के क्षेत्र में परिजन की तलाश और स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर बालक के परिजन की जानकारी मिली की रेलवे स्टेशन प्लेट फार्म नंबर एक के पास का रहने वाला है।

कोटा स्टेशन के प्लेटफॉर्म-2 पर 23 नवंबर से 15 दिन का ब्लॉक, जबलपुर-अजमेर एक्सप्रेस ट्रेनों के मार्ग परिवर्तन

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**



पश्चिम मध्य रेल के कोटा रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास कार्यों के अगले चरण में प्लेटफॉर्म क्रमांक-2 पर आवश्यक निर्माण कार्य किया जाना है। इस कार्य के लिए 23 नवंबर से 7 दिसंबर 2026 तक (15 दिन) का ब्लॉक लिया गया है। इसके चलते चार ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है तथा चार ट्रेनों के प्रारंभिक एवं अंतिम स्टेशन में अस्थायी बदलाव किया गया है। ब्लॉक अवधि के दौरान कोटा स्टेशन का प्लेटफॉर्म क्रमांक-2 रेल परिचालन के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा। यात्रियों की सुविधा एवं सुचारु रेल परिचालन को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रेनों को कोटा के स्थान पर सोगरिया स्टेशन से संचालित किया जाएगा तथा कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। भोपाल मंडल से संबंधित परिवर्तित मार्ग की ट्रेनें 1. गाड़ी संख्या 14814 भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस यह ट्रेन 23 नवंबर से 7 दिसंबर 2026 तक परिवर्तित मार्ग सोगरिया-चम्बल केबिन-गुरला होकर संचालित होगी। इस दौरान ट्रेन कोटा स्टेशन नहीं जाएगी। ट्रेन का सोगरिया स्टेशन पर अस्थायी ठहराव निर्धारित किया गया है, जहाँ इसका आगमन 02:10 बजे एवं प्रस्थान 02:20 बजे रहेगा। 2. गाड़ी संख्या 14813 जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस यह ट्रेन 23 नवंबर से 7 दिसंबर 2026 तक परिवर्तित मार्ग गुरला-चम्बल केबिन-सोगरिया होकर संचालित होगी। इस दौरान ट्रेन कोटा स्टेशन नहीं जाएगी। ट्रेन का सोगरिया स्टेशन पर अस्थायी ठहराव निर्धारित किया गया है, जहाँ इसका आगमन 23:30 बजे एवं प्रस्थान 23:40 बजे रहेगा। 1. गाड़ी संख्या 12181 जबलपुर-अजमेर एक्सप्रेस 23 नवंबर से 6 दिसंबर 2026 तक परिवर्तित मार्ग सोगरिया-चम्बल केबिन-गुरला होकर संचालित होगी। इसका सोगरिया स्टेशन पर आगमन 06:35 बजे एवं प्रस्थान 06:45 बजे रहेगा। 2. गाड़ी संख्या 1182 अजमेर-जबलपुर एक्सप्रेस 23 नवंबर से 7 दिसंबर 2026 तक परिवर्तित मार्ग गुरला-चम्बल केबिन-सोगरिया होकर संचालित होगी। इसका सोगरिया स्टेशन पर आगमन 21:50 बजे एवं प्रस्थान 22:00 बजे रहेगा।

सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही बरतने वाले विभागों को कारण बताओ नोटिस जारी

भोपाल।कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में एडीएम श्री महेन्द्र कवचे एवं जिला पंचायत सीईओ श्रीमती इला तिवारी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में न करने एवं लगातार लापरवाही करने वाले विभाग उच्च शिक्षा, आयुष, वन विभाग, जीएडी, सामाजिक न्याय विभाग, जेल, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, जल संसाधन विभाग, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन?, खनिज, पर्यटन विभाग, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने 50 दिवस से अधिक समय से लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने तथा अनावश्यक रूप से शिकायतों को अन्य विभागों में हस्तांतरित न करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में सोमवार को कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में समय -सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में एसडीएम एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। सभी विभागीय अधिकारियों को शासन के निर्देशानुसार विभागों में लंबित अनुकंपा नियुक्तियों के प्रकरणों का तत्काल निराकरण करने के भी निर्देश दिए।



ब्रिक्स-2026 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में युवा डॉक्टर दंपति डॉ. आनंद और निकिता के स्टार्टअप ने बढ़ाया भोपाल का मान

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प के तहत देश-विदेश के राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति में बुंदेलखंड के एक छोटे से कस्बे हरपालपुर के इंटरनेशनल लेवलके महिला स्वास्थ्य स्टार्टअप को ग्लोबल बी2बी प्लेटफॉर्म मिला है। प्रतिष्ठित ब्रिक्स सम्मेलन में भोपाल के डॉ. आनंद कुमार चौबे और डॉ. निकिता ने भोपाल का मान विश्व पटल पर बढ़ाया है। देश-विदेश के शीर्ष प्रतिनिधियों और राष्ट्राध्यक्षों के सामने उनके उभरते हुए स्टार्टअप को एक प्रमुख ग्लोबल बी2बी (बिजनेस टू-बिजनेस) प्लेटफॉर्म पर विशेष स्थान प्राप्त हुआ। इस उपलब्धि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष सहयोग रहा। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और सऊदी अरब के साथ-साथ अन्य देशों के प्रतिनिधियों के सामने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के तहत वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया के विजन को साकार करते हुए विभिन्न भारतीय स्टार्टअप्स को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। डॉ. दंपति ने सम्मेलन के दौरान दुनिया भर से आए दिग्गज निवेशकों और विदेशी डेलिगेट्स के सामने इनोवेटिव विजन को प्रदर्शित किया। इसके तहत महिलाओं के लिए विशेष आयुर्वेदिक माल्ट, हार्मोन इंटेलिजेंस और हेयर इंटेलिजेंस से सभी को प्रभावित किया। जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी से प्रशिक्षित इंटरनेशनल वैक्सीन इकोनॉमिक्स फेलो और विश्व स्वास्थ्य संगठन कोलैबोरेटिंग सेंटर आईआईएचएमआर जयपुर के पूर्व छात्र रहे डॉ. आनंद चौबे एवं डॉ. निकिता ने अपने जन स्वास्थ्य अनुभव का उपयोग करते हुए इस स्टार्टअप को स्थापित किया है।

जल संसाधन के स्पोर्ट्स क्लब ने दी सेवानिवृत्ति पर भावभीनी विदाई



भोपाल। म.प्र. जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी एवं स्पोर्ट्स क्लब के संस्थापक सदस्य श्री नीरज कुमार खरे को अधिवार्षिकी आयु पूरी करने पर शासकीय सेवा से सेवानिवृत पर जल संसाधन स्पोर्ट्स क्लब भोपाल द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। इसी प्रकार अधीक्षक एवं क्लब के संस्थापक सदस्य श्री अखिलेश श्रीवास्तव तथा सहायक वर्ग-3 एवं पूर्व खेल संयोजक फुटबॉल संरक्षक सदस्य श्री सुधीर जाटव को भी जल संसाधन स्पोर्ट्स क्लब द्वारा उनकी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम के अंत में दिवंगत खिलाडी स्व. आफताब अहमद को दो मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि भी दी गई।

मुख्यमंत्री ने मंत्रि-परिषद् की बैठक से मंत्रि-गण को दी राज्य सरकार की उपलब्धियों की जानकारी

सुशासन और विकास के नए संकल्पों पर होगी चर्चा, नीति चिंतन शिविर 2 दिसंबर को

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में 2 दिसंबर को नीति चिंतन शिविर होगा। इसमें सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव तथा सभी कलेक्टर्स भी हिस्सा लेंगे। इसमें 2 सत्र होंगे। पहला सत्र समृद्ध मध्यप्रदेश-2047 दस्तावेज पर केन्द्रित होगा। दूसरा सत्र सतत् विकास लक्ष्यों और अन्य विकास संकेतकों पर केन्द्रित होगा। इन सत्रों में नीतिगत एवं क्रियान्वयन चुनौतियों के समाधान, भविष्य के रोडमैप और बीते 3 सालों की उपलब्धियों तथा आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। पहले सत्र में 8 विषयों पर नोडल विभाग द्वारा प्रस्तुतिकरण होंगे। दूसरे सत्र में 8 माड्यूल्स पर नोडल विभाग प्रस्तुतिकरण करेंगे। इस प्रकार एक दिन में कुल 16 स्तंभों और माड्यूल्स पर मंथन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद् की बैठक से पहले मंत्रि-गण को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने मंत्रि-गण से राज्य सरकार द्वारा बीते सप्ताह हासिल की गई विशेष उपलब्धियों की जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को भोपाल के नाथू बरखेड़ा में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स के पहले चरण के कामों के लोकार्पण सहित प्रदेश को मिली इस बड़ी उपलब्धि के लिए बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक अद्भुत परिसर है जहां लगभग सभी प्रकार के खेलों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स से अब अपना भोपाल पूरी मजबूती से अंतर्राष्ट्रीय खेल मानचित्र में स्थापित हो गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स में नवनिर्मित सिंथेटिक टर्फ में महिला एशियन हाकी चैम्पियनशिप-2026 के मैचेस खेले जा रहे हैं। इस चैंपियनशिप में 6 एशियाई देशों- भारत, चीन, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया की महिला हाकी टीमें अपना प्रदर्शन कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने स्वयं 22 नवम्बर को मैदान में मैच देखा और खेल का आह्लाद महसूस किया। उन्होंने बताया कि भारतीय टीम ने अपने शुरुआती दोनों मैच जीत कर शानदार बढ़त बना ली है। खचाखच भरे स्टेडियम में दर्शकों का उत्साह भी हर रोज चरम पर दिखाई दे रहा है। मध्यप्रदेश में खेलों की दृष्टि से ये स्वर्णयुग का आगमन है। मुख्यमंत्री ने मंत्रि-गण एवं प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील की कि भोपाल में पहली बार हो रही इस एशियन चैंपियनशिप के मैचों का भरपूर आनंद लें। सिंथेटिक हॉकी टर्फ, सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रेक, प्रेक्टिस फील्ड और दर्शक दीर्घा का निर्माण पहले चरण में किया गया है।



2027 में मप्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा दो बार होगी, कैलेंडर जारी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमने अगले वर्ष (2027) को युवा वर्ष घोषित करने के साथ ही युवाओं से वादा किया है कि प्रदेश में अगले साल मप्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा दो बार आयोजित की जाएगी। हमने अपना वादा पूरा किया है। मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा अगले साल ली जाने वाली परीक्षाओं का समवेत कैलेंडर जारी कर दिया गया है।? यह हम सबके लिए प्रसन्नता का अवसर है कि प्रदेश के युवाओं को उनकी प्रतिभा और योग्यता प्रदर्शन के लिए दो बार अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मंत्रि-गण यह सुनिश्चित करा लें कि रिक्त पदों का मांग-पत्र निर्धारित प्रारूप में आयोग तक समय पर पहुंच जाए, ताकि आयोग परीक्षाओं का विस्तृत विज्ञापन जारी कर सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-गण से कहा कि मध्यप्रदेश की भूमि में देश का पहला टेलिकाम मैन्यूफैक्चरिंग जोन के पहले चरण के तहत पात्र 25 कंपनियों को भूखंड आवंटित कर दिए गए हैं। इस परियोजना के दूसरे चरण के लिए 450 हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर विकसित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस टेलिकॉम मैन्यूफैक्चरिंग जोन से करीब 28000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्वालियर में 170 एकड़ में देश का पहला इंटीग्रेटेड टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित किया जा रहा है। पहले चरण के लिए ग्वालियर टीएमजेड के लिए 25 निवेशकों ने 3,600 करोड़ रूपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव दिए। टीएमजेड की स्थापना के लिए जुलाई 2026 में भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय के साथ एमओयू हुआ था। मात्र 4 से 5 महीने में पहले फेज के लिए आवंटन जारी कर दिया गया। पच्चीस कंपनियों को आशय पत्र वितरित किए गए है।

स्वामी एक सत प्रयास जनकल्याण समिति के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक अमित शर्मा द्वारा शॉप न. 4 केशव कॉलोनी, भोज भवन के पास, मुरैना पिन कोड 476001 मप्र से प्रकाशित एवं भास्कर पब्लिकेशन एंड एलाइड प्रा.लि. बाराघाटा इंडस्ट्रियल एरिया, झांसी रोड ग्वालियर मप्र पिन कोड 474001 से मुद्रित
RNI- MPHIN/26/A8892 संपादक पंकज शर्मा मोबाइल 9926253853 समूह संपादक राजीव शुक्ल, संपर्क : 0755-4515227, ईमेल eksatbulletin@gmail.com